मुंबई(महाराष्ट्र) से प्रकाशित

हिन्दी दैनिक

उत्तरशक्ति

मुंबई
वर्षः 8 अंक 156
गुरुवार, 18 दिसम्बर 2025
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

हर खबर निष्पक्षता के साथ

नेशनल हेराल्ड मामले में विपक्षी सांसदों ने किया संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। बुधवार को कई विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसदों ने सत्यमेव जयते; सत्य की जीत! के नारे वाले पोस्टर पकड़े हुए थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी नेशनल हेराल्ड में सरकार द्वारा अपनाई जा रही प्रतिशोधात्मक राजनीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। इससे पहले आज, कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने बेलगावी के सुवर्ण सौधा स्थित गांधी प्रतिमा के पास नेशनल हेराल्ड मामले और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का नाम बदलकर वीबी-जी राम जी रखने के केंद्रीय सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

विरोध प्रदर्शन के दौरान, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि नेशनल हेराल्ड भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड देश का गौरव है, जिसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की थी और इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाया। शिवकुमार ने कहा कि न्याय की जीत हुई है। भाजपा को यह प्रतिशोधी राजनीति बंद करनी चाहिए।

इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड मामले को सत्ताधारी सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है और दावा किया कि यह मामला केवल गांधी परिवार को परेशान करने के उद्देश्य से रचा गया है। इस मुद्दे पर मीडिया को संबोधित करते हुए खर्गे ने कहा कि आरोपों का कोई आधार नहीं है और दावा किया कि इस मामले में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज नहीं की गई है।

खरगे ने कहा कि वे यह सब राजनीतिक प्रतिशोध के लिए कर रहे हैं। यह मामला केवल गांधी परिवार को परेशान करने के लिए है। इस मामले में कोई एफआईआर नहीं है... हमारा नारा है 'सत्यमेव जयते', और हम इस मामले में आए फैसले का स्वागत करते हैं। मंगलवार को दिल्ली की अदालत ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अभियोजन शिकायत का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अनुसूचित (आधारभूत) अपराध के लिए एफआईआर के अभाव में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती।

नेशनल हेराल्ड मामले में फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए: खड़गे

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पांच अन्य के खिलाफ धन शोधन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से अदालत द्वारा इनकार किए जाने का हवाला देते हुए बुधवार को कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए।

खरगे ने यह आरोप भी लगाया कि यह मामला गांधी परिवार को परेशान करने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध के तहत दर्ज कराया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पांच अन्य के खिलाफ धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

खरगे ने संवाददाताओं से कहा, यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध के तहत दर्ज किया गया है... यह गांधी परिवार को सताने के लिए किया गया है। इसमें कुछ भी नहीं है और कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में फैसला आने के बाद अब नरेन्द्र मोदी और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा, यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के मुंह पर तमाचा है। उन्हें एक राजीनामा देना चाहिए कि भविष्य में वे लोगों को सताने का काम नहीं करेंगे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि जांच एजेंसियों का कैसे दुरुपयोग किया जाता है, नेशनल हेराल्ड मामला इसका एक प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न तो पैसे का कोई लेनदेन हुआ है और ना ही संपत्ति का कोई हस्तांतरण हुआ है तो फिर धन शोधन का सवाल कहां उठता है।

हमारी सरकार ने समृद्ध व विकसित राजस्थान की सशक्त बुनियाद रखी: भजनलाल शर्मा

बीकानेर, 17 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कहा कि भाजपा सरकार गरीब को गणेश मानकर सेवक के रूप में काम कर रही है। शर्मा बीकानेर के लूणकरणसर में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखें। हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बजट दिया और हर विधानसभा क्षेत्र में विकास रथ के माध्यम से विकास कार्यों का लेखा-जोखा जनता तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने दो साल में राज्य में सुशासन, जनकल्याण और चहुंमुखी विकास के लिए ऐसे अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, जो ऐतिहासिक होने के साथ ही समृद्ध एवं विकसित राजस्थान की एक सशक्त बुनियाद भी हैं।

आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसान, युवा, महिला और गरीब के उत्थान के लिए कईकदम उठाए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 612 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं 107 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने बीकानेर की जिला विकास पुस्तिका, ग्रामीण सेवा शिविर की सफलता की कहानी तथा ह्यशहरी सेवा शिविर-2025 पुस्तिका का विमोचन भी किया।

वाराणसी की सड़कों पर उतरे पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, यातायात व्यवस्था को लेकर दिए सख्त निर्देश

- कज्जाकपुरा, चौकाघाट और पाण्डेयपुर चौराहों का किया स्थलीय निरीक्षण, नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश

सुरेश गांधी

वाराणसी। शहर में सुगम, सुरक्षित और निर्बाध यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट मोहित अग्रवाल ने बुधवार को प्रमुख चौराहों एवं मार्गों का भ्रमण कर विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यातायात की व्यवहारिक स्थिति, ट्रैफिक फ्लो, पार्किंग व्यवस्था, डायवर्जन तथा आमजन को हो रही असुविधाओं का गहन अवलोकन किया।

पुलिस आयुक्त ने कज्जाकपुरा क्रॉसिंग पर लागू यातायात व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा करते हुए अनधिकृत कट, गलत दिशा में चलने वाले वाहनों और यातायात अवरोध उत्पन्न करने वाले बिंदुओं पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि निर्धारित यातायात व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन कराया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

चौकाघाट क्षेत्र में ऑटो एवं ई-रिक्शा की पार्किंग व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण करते हुए पुलिस आयुक्त ने यातायात पुलिस को निर्देशित किया कि अनधिकृत पार्किंग पर तत्काल कार्रवाई की जाए तथा पार्किंग व्यवस्था की नियमित निगरानी सुनिश्चित हो, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति न बने।

इसी क्रम में पाण्डेयपुर चौराहे पर यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए बैरिकेडिंग, लेन मैनेजमेंट और पुलिस बल की प्रभावी तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पुलिस आयुक्त ने कहा कि पीक आवर्स के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाए और जाम की स्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए।

पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने दो टूक कहा कि शहर में सुगम यातायात के लिए लागू की जा रही सभी स्थानीय व्यवस्थाओं का प्रभावी, सतत और शत-प्रतिशत अनुपालन अनिवार्य है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस को आपसी समन्वय के साथ निरंतर मॉनिटरिंग करते हुए त्वरित सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए।इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने आम नागरिकों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें, गलत दिशा में वाहन न चलाएं, निर्धारित पार्किंग का ही उपयोग करें और यातायात सुधार के लिए किए जा रहे पुलिस प्रशासन के प्रयासों में सहयोग करें, ताकि शहर में सभी के लिए सुरक्षित और सुचारु आवागमन सुनिश्चित किया जा सके।

निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस उपायुक्त यातायात अंशुमान मिश्रा, सहायक पुलिस आयुक्त यातायात सोमवीर सिंह सिरोही सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

पहली शादी कायम रहने पर महिला दूसरे व्यक्ति से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती : उच्च न्यायालय

इलाहाबाद, 17 दिसम्बर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा है कि एक महिला ने यदि अपने पति से तलाक नहीं लिया है तो उसने दूसरे व्यक्ति के साथ कितना लंबा समय क्यों ना व्यतीत किया हो, वह उससे सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता का दावा नहीं कर सकती।

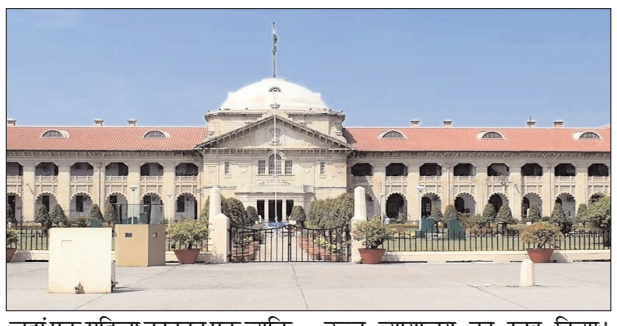

अदालत ने स्पष्ट किया, भले ही मान लिया जाए कि विवाह की रस्म हुई है, तो भी यह अमान्य होगा क्योंकि याचिकाकर्ता का पूर्व का विवाह अस्तित्व में बना हुआ है। इसलिए वह लंबे समय से संबंध के आधार पर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता का दावा नहीं कर सकती।

न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की पीठ ने कहा, यदि समाज में इस तरह की व्यवस्था की अनुमति दी जाती है जहां एक महिला कानूनन एक व्यक्ति की पत्नी है और बिना तलाक लिए वह दूसरे व्यक्ति के साथ रहती है और दूसरे व्यक्ति से गुजारा भत्ता की मांग करती है तो धारा 125 की पवित्रता और उद्देश्य खत्म हो जाएगा और विवाह नाम की संस्था अपनी कानूनी और सामाजिक निष्ठा खो देगी।

मौजूदा मामले में महिला ने जिला अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया। जिला अदालत ने भी गुजारा भत्ता का आदेश देने से इनकार कर दिया था।

पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा, इस अदालत का विचार है कि यद्यपि याचिकाकर्ता विपक्षी के साथ करीब 10 वर्ष रही और यह संबंध वैवाहिक संबंध जैसा प्रतीत हो सकता है, फिर भी इस तरह से साथ रहना, उसे धारा 124 के तहत एक पत्नी का कानूनी दर्जा प्रदान नहीं करता। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि महिला का नाम उसके आधार कार्ड और पासपोर्ट सहित आधिकारिक दस्तावेज में विपक्षी (जिसके साथ वह रहती थी) की पत्नी के तौर पर दर्ज है और समाज में उसे विपक्षी की पत्नी के तौर पर पहचाना जाता है। उन्होंने दलील दी कि विपक्षी और उसके बेटों ने महिला के साथ क्रूरता और उत्पीड़न किया और उसे मार्च, 2018 में घर से निकाल दिया जिससे वह धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता की मांग करने के लिए विवश हुई।

अदालत ने आठ दिसंबर को दिए अपने निर्णय में कहा कि याचिकाकर्ता धारा 125 के तहत कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के दायरे में नहीं आती, इसलिए गुजारा भत्ता की मांग का उसका आवेदन खारिज किया जाता है।

अब पराली नहीं जलाई जा रही फिर भी दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट क्यों: मुख्यमंत्री मान

पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा और कहा कि उसके (भाजपा के) नेता पराली जलाने को लेकर पंजाब के किसानों को बदनाम करते थे और दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता के लिए उन्हें दोषी ठहराते थे, लेकिन अब यहां कोई पराली नहीं जलाई जा रही फिर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का संकट क्यों है। मान ने कहा कि धान की कटाई होते ही भाजपा नेता दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता के लिए पंजाब और उसके किसानों को दोषी ठहराने लगते थे। उन्होंने कहा कि वे पहले दावा करते थे कि पंजाब के किसानों द्वारा पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण होता है।

अमीरी की जीवनशैली, प्रदूषण का बोझ और गरीब की त्रासदी

-ललित गर्ग

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आज जिस घातक पर्यावरण संकट से गुजर रही है, वह केवल एक शहर की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश के लिये चेतावनी है। विडंबना यह है कि इस संकट के नाम पर जो तात्कालिक उपाय लागू किए जाते हैं, उनका सबसे बड़ा खामियाजा वही तबका भुगतता है, जिसकी इसमें सबसे कम भूमिका होती है-गरीब और श्रमिक वर्ग। इसी पीड़ा को शब्द देते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अमीरों की जीवनशैली से पैदा हुई मुश्किलों का सामना गरीबों को करना पड़ता है। यह टिप्पणी न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और नैतिक चेतना को झकझोरने वाली भी है। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह मर्मस्पर्शी टिप्पणी की। वरिष्ठ अधिवक्ता और न्यायमित्र अपराजिता सिंह की दलीलों पर गौर करते हुए अदालत ने स्पष्ट कहा कि ग्रैप-4 जैसी सख्त पाबंदियों का सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ता है। निर्माण कार्य रुकते हैं, दिहाड़ी मजदूरों की रोजी-रोटी ठप हो जाती है, जबकि प्रदूषण पैदा करने वाली जीवनशैली में शामिल संपन्न तबके पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ता। मुख्य न्यायाधीश ने साफ शब्दों में कहा कि समस्या की जड़ अमीरों की जीवनशैली है और समाधान भी वहीं से शुरू होना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अदालत ऐसे प्रभावी और लागू करने योग्य आदेश पारित करेगी, जिन्हें जरूरत पड़ने पर सख्ती से लागू भी किया जा सकेगा।

जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि महानगरों में लोगों की अपनी अलग जीवनशैली होती है, जिन्हें वे बदलना नहीं चाहते। यही वजह है कि समस्या अमीरी की वजह से होती है, लेकिन झेलना गरीब को पड़ता है। दरअसल, अदालत की सोच रही है कि हमारा परिवेश-पर्यावरण साफ-सुथरा रहे, इसके लिये हम सबको अपने कुछ सुखों का त्याग करना होगा, अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल ढालना होगा एवं प्रकृति-एवं पर्यावरण के प्रति सकारात्मक रवैया अपना होगा। यह जानते हुए कि पर्यावरण पर आने वाले संकट व प्रदूषित हवा का अमीर-गरीब पर समान असर पड़ता है फिर भी अमीर लोग इससे बेपरवाह रहते हैं। निस्संदेह, शीर्ष अदालत ने समाज की दुखती रग पर हाथ रखा है। चौड़ी होती सड़कें, नए फ्लाईओवर और हाईवे बनने के बावजूद जाम और प्रदूषण कम नहीं हो रहे। कारण साफ है निजी वाहनों का बेहिसाब इस्तेमाल। एक व्यक्ति, एक कार का चलन न केवल सड़क की जगह घेरता है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को भी कई गुना बढ़ाता है। कभी ऑड-इवन जैसी योजनाओं पर चर्चा हुई, कार-पूलिंग की बात चली, लेकिन सार्वजनिक परिवहन को सस्ता, सुगम और भरोसेमंद बनाने की इच्छाशक्ति लगातार कमजोर रही।

आज एसी, कूलर और अन्य वातानुकूलन साधनों का बढ़ता उपयोग भी पर्यावरण संकट को गहराता जा रहा है। इससे बिजली की खपत बढ़ती है, तापमान में वृद्धि होती है और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण का दायरा फैलता है। उद्योगों में भी पर्यावरणीय नियमों का ईमानदार पालन नहीं होता। जल संकट इसका एक और क्रूर उदाहरण है-जहां झुग्गी-बस्तियों में पीने के पानी की किल्लत है, वहीं पॉश कॉलोनियों में लॉन सींचे जाते हैं, कारें धुलती हैं और स्विमिंग पूल भरे रहते हैं। कुदरत ने हवा, पानी और संसाधन सभी के लिये दिए हैं, लेकिन अमीरी के असमान दखल ने इनके वितरण को अन्यायपूर्ण बना दिया है। राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप तो करते हैं, लेकिन ठोस और दीर्घकालिक समाधान सामने नहीं आते।

अब समय आ गया है कि सरकार और जनता-दोनों अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएं। सरकार को सार्वजनिक परिवहन को मजबूत, सस्ता और आकर्षक बनाना होगा, उद्योगों पर पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन कराना होगा और शहरी विकास की नीतियों को पर्यावरण-संवेदनशील बनाना होगा। वहीं जनता को भी अपनी जीवनशैली पर पुनर्विचार करना होगा-अनावश्यक वाहन उपयोग से बचना, ऊर्जा की खपत कम करना, एसी और अन्य सुविधाओं का संयमित इस्तेमाल करना और साझा संसाधनों के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाना होगा। विडंबना यह है कि सत्ताधीशों ने दिल्ली में सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को सशक्त करने को प्राथमिकता नहीं दी। यदि सार्वजनिक परिवहन सस्ता व सहज उपलब्ध होता तो शायद सड़कों पर कारों का दबाव कम होता। हाल के दिनों में संपन्न व मध्यम वर्ग में एसी व अन्य वातानुकूलन उपायों के उपयोग का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। इससे जहां प्रदूषण बढ़ाने वाली बिजली की खपत बढ़ी है, वहीं बाहर का तापमान व कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ा है। इसी तरह तमाम अमीरों द्वारा संचालित उद्योगों में उन उपायों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया जो पर्यावरण में प्रदूषण कम करने में सहायक होते हैं।

सरकारों की नीतिगत विफलता इस बढ़ते वायु प्रदूषण की त्रासदी का बड़ा कारण है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए योजनाएं तो बनती हैं, पर उनमें न तो स्थायित्व होता है, न गंभीरता। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, निगरानी तंत्र कमजोर है, और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई नगण्य है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जिम्मेदारी का बंटवारा अस्पष्ट है। हर साल सर्दियों में दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य शहरों की हवा जहरीली हो जाती है, तब कुछ दिन के लिए ह्यआपात कदमह्न उठाए जाते हैं, पर जैसे ही धुंध छंटती है, सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाता है। नीतियों में पारदर्शिता का अभाव और उद्योगपतियों का दबाव भी एक गहरी समस्या है। कोयला आधारित उद्योगों, पेट्रोलियम कंपनियों और निर्माण व्यवसाय से जुड़ी लॉबी सरकारों पर ऐसा प्रभाव बनाए रखती हैं कि कठोर कदम उठाना राजनीतिक दृष्टि से असुविधाजनक बन जाता है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण को हमेशा ह्यमहंगा विकल्पह्न बताकर टाला जाता है, जबकि वास्तव में यह निवेश मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा में है।

वायु प्रदूषण का संकट केवल वातावरण में धूल और धुएं का मामला नहीं है, यह आर्थिक अन्याय, राजनीतिक असंवेदनशीलता और सामाजिक उदासीनता का प्रतीक बन चुका है। जो सरकारें जनजीवन सुधारने का वादा करती हैं, वे हवा की गुणवत्ता सुधारने में विफल रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि वायु प्रदूषण से भारत की अर्थव्यवस्था को हर साल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दस प्रतिशत तक का नुकसान हो रहा है। यह नुकसान केवल पैसों में नहीं, बल्कि मानव संसाधन की हानि, स्वास्थ्य पर बोझ और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट के रूप में भी दिखाई देता है। अब समय है कि इस संकट को केवल पर्यावरणीय मुद्दा न मानकर एक सामाजिक और नैतिक चुनौती के रूप में देखा जाए। हवा का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन यह अधिकार धीरे-धीरे छिनता जा रहा है। अमीरों को अपनी जीवनशैली पर संयम लाना होगा, अपने निवेशों को स्वच्छ ऊर्जा की ओर मोड़ना होगा, और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से दूरी बनानी होगी। सरकारों को सख्त नीति बनानी चाहिए, जो न केवल प्रदूषण फैलाने वालों को दंडित करे बल्कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने वालों को प्रोत्साहन दे।

वायु प्रदूषण एक सामूहिक अपराध बन गया है जिसमें अपराधी कम और पीड़ित अधिक हैं। अब यह वक्त है जब विकास की परिभाषा में स्वच्छ हवा और सुरक्षित वातावरण को सबसे ऊपर रखा जाए। सरकारें यदि सचमुच राष्ट्र की समृद्धि चाहती हैं, नया भारत-विकसित भारत बनाना चाहती है तो उन्हें सांसों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। अमीर तबके को भी यह समझना होगा कि जिस हवा को वे अपने निवेशों से दूषित कर रहे हैं, वह अंततः उन्हीं की अगली पीढ़ियों की सांसों को रोक देगी। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को लेकर किसी किस्म की उदासीनता देश और मानवता के साथ अन्याय होगा। अमीरी होना कोई अपराध नहीं, लेकिन अमीरी की कीमत अगर गरीब चुकाए, तो वह सभ्य समाज की हार है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी और सोच हमें यही संदेश देती है कि स्वच्छ पर्यावरण के लिये कुछ सुखों का त्याग अनिवार्य है। यदि आज हमने अपनी आदतें नहीं बदलीं, तो आने वाली पीढ़ियों को हम केवल प्रदूषित हवा, सूखते जलस्त्रोत और असमानता की विरासत ही सौंप पाएंगे।

संसद का अवरुद्ध स्वर और लोकतंत्र की कसौटी

-प्रियंका सौरभ

लगातार व्यवधानों के दौर में संसदीय लोकतंत्र को सशक्त करने की संस्थागत राह

भारतीय संसद लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है। यही वह मंच है जहाँ जनता की विविध आकांक्षाएँ, असहमतियाँ और अपेक्षाएँ बहस के माध्यम से नीति और कानून का रूप लेती हैं। किंतु हाल के वर्षों में संसद की कार्यवाही बार-बार बाधित होने, प्रश्नकाल के स्थगित रहने, विधेयकों के बिना पर्याप्त चर्चा पारित होने और सदन के समय से पहले स्थगन ने इसकी गरिमा और प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। संसद, जो संवाद और सहमति का प्रतीक होनी चाहिए थी, वह अनेक अवसरों पर टकराव और अवरोध का अखाड़ा बनती दिखी है। यह स्थिति केवल संसदीय परंपराओं का क्षरण नहीं, बल्कि प्रतिनिधि लोकतंत्र की जड़ों के कमजोर होने का संकेत भी है।

संसद में व्यवधान कोई नया विषय नहीं है। विरोध, असहमति और सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रतिपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में अनिवार्य है। किंतु जब विरोध का प्रमुख औजार निरंतर हंगामा, नारेबाजी और कार्यवाही ठप करना बन जाए, तब यह प्रश्न उठता है कि क्या संसद अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर पा रही है। बार-बार स्थगित होने वाली कार्यवाही का सबसे बड़ा नुकसान जनता को होता है, क्योंकि संसद का हर खोया हुआ घंटा नीतिगत विमर्श, जनहित के मुद्दों और विधायी समीक्षा से चूक का प्रतीक बन जाता है। यह स्थिति कार्यपालिका को अधिक शक्तिशाली बनाती है और विधायिका की निगरानी भूमिका को कमजोर करती है।

लोकतांत्रिक शासन में संसद केवल कानून पारित करने की मशीन नहीं होती, बल्कि वह कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने, नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा करने और समाज के विभिन्न वर्गों की आवाज को सामने लाने का मंच भी होती है। जब संसद बाधित होती है, तब कार्यपालिका पर सवाल पूछने के अवसर कम होते हैं, अध्यादेशों और ह्यगिलोटिनह्न जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से विधायी निगरानी कमजोर पड़ती है और निर्णय कुछ सीमित हाथों में केंद्रित होने लगते हैं। इस संदर्भ में संस्थागत सुधारों की आवश्यकता केवल तकनीकी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक नैतिकता से जुड़ा प्रश्न है।

संसदीय समितियों की भूमिका इस बहस में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में संसदीय समितियाँ सदन के बाहर अपेक्षाकृत शांत वातावरण में विधेयकों की बारीकी से जांच करने, विशेषज्ञों और हितधारकों की राय लेने तथा राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर व्यावहारिक सुझाव देने का मंच प्रदान करती हैं। जब अधिकाधिक विधेयकों को बिना समिति जांच के पारित किया जाता है, तो कानून निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। संस्थागत सुधार के रूप में सभी प्रमुख विधेयकों को अनिवार्य रूप से समितियों को भेजना न केवल विधायी प्रक्रिया को मजबूत करेगा, बल्कि संसद के भीतर होने वाले टकराव को भी कम कर सकता है, क्योंकि असहमति का समाधान बहस और प्रमाण के माध्यम से बाहर संभव होगा।

प्रश्नकाल को संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है। यही वह समय होता है जब निर्वाचित प्रतिनिधि सीधे-सीधे मंत्रियों से जनता से जुड़े सवाल पूछते हैं और सरकार को अपने निर्णयों का स्पष्टीकरण देना पड़ता है। प्रश्नकाल का बार-बार बाधित होना या औपचारिकता में सिमट जाना कार्यपालिका की जवाबदेही को कमजोर करता है। संस्थागत सुधार के तहत प्रश्नकाल की सुरक्षा और उसकी अनिवार्यता तय करना आवश्यक है, ताकि किसी भी परिस्थिति में इसे स्थगित न किया जाए। इससे सरकार और विपक्ष दोनों को संवाद के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

संसद में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए आचार-संहिता और दंडात्मक प्रावधान भी आवश्यक हैं। वर्तमान में नियम तो मौजूद हैं, किंतु उनका निष्पक्ष और सुसंगत क्रियान्वयन अक्सर विवादों में घिर जाता है। यदि सांसदों के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और सर्वसम्मति से तय आचार-संहिता हो तथा उसके उल्लंघन पर समान रूप से कार्रवाई हो, तो अव्यवस्थित आचरण पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। यह सुधार केवल दंड देने का नहीं, बल्कि संसदीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने का माध्यम बन सकता है।

संसद के कार्यदिवसों की संख्या भी एक महत्वपूर्ण संस्थागत मुद्दा है। भारत की संसद कई विकसित लोकतंत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम दिन बैठती है। सीमित सत्रों में भारी विधायी एजेंडा न केवल सांसदों पर दबाव बढ़ाता है, बल्कि सार्थक बहस की संभावना को भी कम करता है। न्यूनतम निश्चित बैठक दिनों वाला कैलेंडर तय करना और उसका सख्ती से पालन करना विधायी गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। अधिक बैठकों का अर्थ केवल अधिक कानून नहीं, बल्कि अधिक संवाद, अधिक प्रश्न और अधिक जवाबदेही है।

हालाँकि, इन संस्थागत सुधारों की राह आसान नहीं है। राजनीतिक दल अक्सर संसद के भीतर व्यवधान को एक वैध राजनीतिक हथियार मानते हैं। विपक्ष को यह आशंका रहती है कि सुधारों के नाम पर उसके विरोध के अधिकार को सीमित किया जाएगा, जबकि सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगता है कि वह संस्थागत नियमों का उपयोग असहमति को दबाने के लिए कर सकता है। इसके अतिरिक्त, स्पीकर या सभापति की निष्पक्षता पर उठने वाले सवाल भी सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा बनते हैं। यदि पीठासीन अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगे, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी विवाद का कारण बन जाती है।

कार्यपालिका का बढ़ता प्रभुत्व भी एक गंभीर चिंता है। अध्यादेशों का बढ़ता प्रयोग, धन विधेयकों के दुरुपयोग और समयाभाव के नाम पर बहस सीमित करने की प्रवृत्ति संसद की भूमिका को कमजोर करती है। ऐसे में केवल नियम बदलना पर्याप्त नहीं होगा; सत्ता और विपक्ष दोनों को संसदीय मर्यादाओं के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी होगी। संस्थागत सुधार तभी सार्थक होंगे जब उन्हें राजनीतिक इच्छाशक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन प्राप्त हो।

अंततः संसद की मजबूती किसी एक सुधार या नियम से सुनिश्चित नहीं हो सकती। यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें संस्थाएँ, परंपराएँ और राजनीतिक आचरण तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। संसद को फिर से बहस, सहमति और उत्तरदायित्व का मंच बनाने के लिए आवश्यक है कि विरोध संवाद में बदले, असहमति अवरोध में नहीं, और शक्ति संतुलन संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बना रहे। तभी भारतीय संसदीय लोकतंत्र न केवल व्यवधानों से उबर पाएगा, बल्कि एक जीवंत, प्रतिनिधिक और जवाबदेह संस्था के रूप में अपनी भूमिका को पुनः स्थापित कर सकेगा।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा पर सबसे बड़ा संकट

-नर्मल रानी

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष में दुनिया की सबसे जटिल समझी जाने वाली चुनावी प्रक्रिया को अपनाने व इसे पूरा कराने को लेकर जिस केंद्रीय चुनाव आयोग की पीठ पूरी दुनिया थपथपाया करती थी व दुनिया के विभिन्न देशों के संसदीय प्रतिनिधिमंडल व चुनाव विशेषज्ञ जिस भारतीय चुनाव संचालन को देखने व समझने के लिये अब भी भारत आते रहते हैं वही चुनाव व चुनाव आयोग इन दिनों विपक्षी दलों के अति गंभीर आरोपों से जूझ रहा है। चुनाव आयोग व इस तरह के कई अन्य केंद्रीय संस्थानों पर सत्ता का पक्षपात करने के आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं। परन्तु वर्तमान चुनाव आयोग जिसतरह सत्ता को फायदा पहुँचाने वाले नए नए चुनावी नियम बना रहा है,विपक्ष की प्रमाण सहित दी जाने वाली शिकयतों की अनसुनी कर रहा है,सत्ता द्वारा चुनाव आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाने के बावजूद आँखें मूंदे बैठा रहता है,और अब एस आई आर के बहाने कथित तौर पर जहाँ करोड़ों फर्जी मतों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है वहीँ संभावित रूप से विपक्ष की ओर जाने वाले मतों को चिन्हित कर उन्हें किसी न किसी बहाने से मतदाता सूची से काटने का काम किया जा रहा है। यानी स्पष्ट रूप से लोकततंत्र में लोक के मताधिकार पर 'डाका ' डाला जा रहा है।

वैसे तो पूरा विपक्ष ही चुनाव आयोग को केवल संदेह नहीं बल्कि सत्ता से मिलकर संविधान के साथ विश्वासघात किये जाने की दृष्टि से देख रहा है। लोक सभा व राज्य सभा के सर्वोच्च सदनों में चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। परन्तु नेता विपक्ष राहुल गाँधी ने तो चुनाव आयोग द्वारा की और करायी जाने वाली धांधली पर तो बाकायदा 'शोध' कर डाला है। और वे अपने इस चुनाव धांधली सम्बन्धी 'शोध परिणाम' को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शित करने से लेकर जनता जनार्दन के बीच सड़कों व गलियों तक पहुँच रहे हैं। इस संबंध वे अब तक 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 'वोट चोरी ' के पूरे सबूत पेश कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे अगस्त-सितंबर 2025 के बीच बिहार में 16 दिनों की 1,300 किमी लंबी वोटर अधिकार यात्रा भी रक्फ़के विरुद्ध निकाल चुके हैं। इसके अलावा 200 से अधिक सांसदों व विधायकों के साथ वे 11 अगस्त 2025 को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्यालय तक एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन रुपी पैदल मार्च भी कर चुके हैं। एक ओर तो राहुल चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये डेटा के अनुसार ही आयोग द्वारा बरती गयी अनियमितताओं संबंधी साक्ष्य पेश करते हैं तो दूसरी ओर चुनाव आयोग कभी इन आरोपों को बेबुनियाद बता कर अपना पल्ला झाड़ लेता है तो कभी उल्टे राहुल से ही शपथ-पत्र मांगने लगता है।

परन्तु लगता है कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने तो गोया चुनाव आयोग को पूरी तरह बेनकाब करने का संकल्प ही कर लिया है। गत 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने एक विशाल रैली आयोजित की। ₹वोट चोर, गद्दी छोड़₹ के शीर्षक से किये गये इस आयोजन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशभर से लाखों कार्यकर्ता जुटाये। इस रैली का भी मुख्य उद्देश्य हरियाणा, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में हाल के विधानसभा चुनावों में कथित वोट चोरी और मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप लगाना था। इस विशाल रैली में भी कांग्रेस ने भाजपा और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाते हुए लोकतंत्र तथा संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। इस तरह की किसी रैली में यह पहला मौका था जब कि सीधे तौर पर सबसे तीखा हमला मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके दो आयुक्तों पर बोला गया। सांसद प्रियंका गाँधी ने एक बार और राहुल गांधी ने तो दो बार अपने भाषण में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी का नाम लेकर उनपर सीधे निशाना साधा। इन नेताओं ने उनका नाम लेते हुये आरोप लगाया कि 'चुनाव आयोग भाजपा सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है, वोट चोरी को संरक्षण दे रहा है तथा आयोग निष्पक्ष नहीं है। ये लोग नहीं भूलें कि वे देश के चुनाव आयुक्त हैं, नरेंद्र मोदी के नहीं।₹राहुल ने यह भी कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयुक्तों को कानूनी सुरक्षा (इम्यूनिटी) देने वाला कानून बदला है, ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सके। कांग्रेस सत्ता में आने पर इस कानून को बदलेगी और आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। यहाँ भी राहुल ने दोहराया कि ₹चुनाव आयोग असत्य के साथ खड़ा नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे हरियाणा में चुनाव चोरी हुआ, किस तरह कर्नाटक में लाखों वोट डिलीट हुए और महाराष्ट्र में फर्जी वोट जोड़े गए परन्तु चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया।₹ यहाँ भी राहुल ने चुनावी धांधलियों के कई और उदाहरण पेश किये। यही नहीं बल्कि राहुल गांधी द्वारा देश भर से चुनाव आयोग के विरुद्ध लगभग 6 करोड़ हस्ताक्षर कराए गए हैं। यह अभियान कथित वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ चलाया गया था, और इन हस्ताक्षरों को राष्ट्रपति को सौंपने की योजना है। इन 6 करोड़ हस्ताक्षर को भी 14 दिसंबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली के दौरान प्रदर्शित किया गया।

इसी रैली में कांग्रेस के कई प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया को हर कदम पर संदिग्ध बताते हुये संस्थाओं पर दबाव डालने का आरोप लगाया जबकि कुछ वक्ताओं ने चुनाव आयोग को भाजपा की कठपुतली बताते हुये आयोग पर सबूतों की जांच नहीं करने का भी आरोप लगाया। कुछ नेताओं का मत था कि देश में निष्पक्ष अंपायर की कमी है। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो मुख्य रूप से भाजपा पर ₹वोट चोरी₹ करके सत्ता में आने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह रैली कांग्रेस की ओर से चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ अब तक का एक सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन थी, जिसमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सार्वजनिक रूप से खुलकर गंभीर सवाल उठाए गए। साथ ही यह भी सच है कि चुनाव आयोग पर प्रमाण सहित लगने वाले इसतरह के आरोपों और आयोग द्वारा इन आरोप को नजर अंदाज करने से भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा यहाँ पर भी सबसे बड़ा संकट सामने आ खड़ा हुआ है।

लोकसभा में जी राम जी बिल पेश-संसद में घमासान

किशन भावनानी

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था दशकों से संरचनात्मक चुनौतियों, बेरोजगारी अस्थायी आजीविका और कृषि-आधारित जोखिमों से जूझती रही है। वर्ष 2005 में लागू किया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) इन चुनौतियों के विरुद्ध एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप था, जिसने पहली बार ग्रामीण नागरिकों को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया। अब संसद में पेश किया गया विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी रामजी) बिल न केवल इस कानून को समाप्त करता है, बल्कि ग्रामीण रोजगार की अवधारणा को एक नए वैधानिक ढांचे में पुनर्परिभाषित करने का दावा करता है। यही कारण है कि यह विधेयक नीतिगत से अधिक राजनीतिक, वैचारिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन गया है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यदि हम इसको संवैधानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो,मनरेगा ने अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) और अनुच्छेद 39 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) की भावना को व्यावहारिक रूप दिया था। यदि नया कानून अधिकार आधारित नहीं रहता,तो यह प्रश्न उठेगा कि क्या यह संविधान की सामाजिक न्याय की भावना से पीछे हटना है। यह मुद्दा भविष्य में न्यायिक समीक्षा का विषय भी बन सकता है।

साथियों बात अगर हम वीबी-जी रामजी बिल क्या है,एक नया कानूनी ढांचा इसको समझने की करें तो,वीबी-जी रामजी बिल का पूरा नाम विकसित भारतरोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) बिल है। सरकार के अनुसार यह कानून विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को केवल अस्थायी रोजगार नहीं, बल्कि स्थायी आजीविका, कौशल -आधारित रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाना है। इस बिल के तहत ग्रामीण परिवारों को गारंटी वाले काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 करने का प्रस्ताव है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की वार्षिक आय में वृद्धि का दावा किया जा रहा है। मनरेगा को समाप्त कर नया कानून ऐतिहासिक बदलाव,यह बिल संसद में प्रस्तुत होते ही इसलिए विवादों में आ गया क्योंकि यह 2005 के मनरेगा अधिनियम को पूरी तरह समाप्त कर देता है। मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और अधिकार आधारित कानून के रूप में स्थापित रहा है। इसमें काम का अधिकार, समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता, और पारदर्शिता के लिए सामाजिक अंकेक्षण जैसे प्रावधान शामिल थे। वीबी-जी रामजी बिल इन प्रावधानों को किस हद तक बनाए रखता है या बदलता है,यही वर्तमान बहस का केंद्र है।गारंटी वाले कार्यदिवस -100 से 125 दिन का प्रस्ताव,सरकार का कहना है कि 125 दिनों की रोजगार गारंटी ग्रामीण परिवारों को अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। यह कदम विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जहाँ कृषि मौसम पर निर्भरता अधिक है और गैर-कृषि रोजगार के अवसर सीमित हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का तर्क है कि दिनों की संख्या बढ़ाना तभी सार्थक होगा जब भुगतान समय पर हो, काम की गुणवत्ता सुनिश्चित हो और बजटीय आवंटन पर्याप्त हो।राज्यों पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ- वीबी -जी रामजी बिल का एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव यह है कि इसमें राज्य सरकारों की वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। मनरेगा में केंद्र सरकार की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक थी, जबकि नए बिल में राज्यों से अधिक खर्च की अपेक्षा की जा रही है। इससे संघीय ढांचे में असंतुलन की आशंका जताई जा रही है, विशेषकर उन राज्यों में जिनकी वित्तीय स्थिति पहले से ही कमजोर है।रोजगार से आजीविका की ओर नीति का झुकाव-सरकार का दावा है कि यह बिल केवल ह्यकाम उपलब्ध करानेह्न तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधनों को विकसित करेगा। इसके अंतर्गत कौशल विकास,स्थानीयसंसाधनों पर आधारित रोजगार, ग्रामीण उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। यह दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई सस्टेनेबल लाइवलीहुड अप्रोच से मेल खाता है।

साथियों बात अगर हम मनरेगा बनाम वीबी-जी रामजी,मूलभूत अंतर को समझने की करें तो, मनरेगा एक अधिकार आधारित कानून था, जिसमें काम मांगने का अधिकार स्पष्ट था। इसके विपरीत, वीबी-जी रामजी बिल को लेकर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह अधिकार आधारित दृष्टिकोण से हटकर मिशन मोड में लागू होने वाली योजना बन सकता है। यदि ऐसा हुआ, तो ग्रामीण श्रमिकों की कानूनी सुरक्षा कमजोर हो सकती है।काम का स्वरूप-अकुशल श्रम से आजीविका तकमनरेगा मुख्यत-अकुशल श्रम पर केंद्रित रहा है,जैसे जल संरक्षण सड़क निर्माण, तालाब खुदाई आदि। इसके विपरीत, वीबी-जी रामजी बिल का दावा है कि वह रोजगार से आगे बढ़कर आजीविका पर ध्यान देगा। इसमें कौशल विकास, स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता को शामिल करने की बात कही गई है। यह बदलाव सैद्धांतिक रूप से सकारात्मक है, लेकिन यह तभी सफल होगा जब जमीनी स्तर पर पर्याप्त प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ाव सुनिश्चित किया जाए।वित्तीय संरचना-केंद्र बनाम राज्य मनरेगा में वित्तीय भार का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार उठाती थी,जिससे राज्यों को अपेक्षाकृत राहत मिलती थी। नए बिल में राज्य सरकारों की वित्तीय हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है। इससे संघीय ढांचे में असंतुलन की आशंका जताई जा रही है, विशेषकर गरीब और पिछड़े राज्यों के लिए। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि क्या सभी राज्य इस बढ़े हुए बोझ को वहन करने में सक्षम होंगे।पारदर्शिता और जवाबदेही,मनरेगा की एक बड़ी ताकत उसका सामाजिक अंकेक्षण तंत्र था, जिसने इसे अपेक्षाकृत पारदर्शी बनाया।वीबी-जी रामजी बिल में इस तरह के स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था कितनी मजबूत होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। यदि जवाबदेही तंत्र कमजोर हुआ,तो भ्रष्टाचार और असमान क्रियान्वयन की आशंका बढ़ सकती है राजनीतिक अर्थव्यवस्था-मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरों को न्यूनतम सुरक्षा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग को बनाए रखा। नया कानून यदि इस सुरक्षा को कमजोर करता है, तो इसका प्रभाव केवल मजदूरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सरकार का दावा है कि आजीविका -केंद्रित मॉडल लंबे समय में अधिक टिकाऊ होगा, लेकिन अल्पकालिक संक्रमण चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

साथियों बात अगर हम महात्मा गांधी का नाम हटाना- प्रतीकात्मक या वैचारिक निर्णय? इसको समझने की करें तो,विधेयक को लेकर सबसे तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया महात्मा गांधी के नाम को हटाने पर आई है। विपक्ष का तर्क है कि गांधी केवल एक नाम नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, श्रम की गरिमा और सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। प्रियंका गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि नाम बदलने से जमीनी समस्याओं का समाधान कैसे होगा,और इससे सरकारी धन का अनावश्यक खर्च क्यों किया जा रहा है।प्रियंका गांधी का बयान,विपक्ष की चिंता का स्वर,प्रियंका गांधी ने इस बिल पर सवाल उठाते हुए कहा कि महात्मा गांधी का नाम न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान का प्रतीक है। उनका कहना है कि जब योजनाओं के नाम बदले जाते हैं, तो सरकारी दफ्तरों, दस्तावेजों और स्टेशनरी में बदलाव पर भारी खर्च आता है,जिसका सीधा लाभ जनता को नहीं मिलता। उन्होंने इसे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला कदम बताया।विपक्ष की आशंकाएँ- अधिकार कमजोर होने का डर-विपक्ष का मुख्य आरोप है कि मनरेगा को खत्म करना गरीबों के अधिकारों को कमजोर करने जैसा है। उनका कहना है कि यदि नया कानून अधिकार आधारित न होकर योजना आधारित हुआ, तो भविष्य में सरकारें इसे आसानी से बदल या सीमित कर सकती हैं।संसदीय बहस और संभावित हंगामा-इन तमाम मुद्दों के चलते संसद में इस बिल पर हंगामेदार बहस की संभावना जताई जा रही है। यह बहस केवल रोजगार नीति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संविधान, संघीय ढांचा, सामाजिक न्याय और गांधीवादी मूल्यों तक जाएगी।

साथियों बात ग्राम सरकार का पक्ष,नई गति और विकसित भारत का लक्ष्य इसको समझने की करें तो,केंद्र सरकार का कहना है कि यह बिल ग्रामीण भारत को ह्यनई गतिह्न देगा और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएगा। सरकार के अनुसार, मनरेगा की सीमाओं को पहचानते हुए यह नया कानून अधिक आधुनिक, परिणाम- उन्मुख और दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत करता है।

साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य -रोजगार गारंटी की वैश्विक प्रासंगिकता इसको समझने की करें तो विश्व स्तर पर रोजगार गारंटी जैसे कार्यक्रमों को सामाजिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है। भारत का यह नया प्रयोग अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर में भी रहेगा कि क्या यह अधिकार आधारित मॉडल से हटकर भी समान या बेहतर परिणाम दे सकता है।'दुनियाँ के कई देशों में रोजगार गारंटी या सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम लागू हैं,लेकिन भारत का मनरेगा मॉडल अधिकार आधारित होने के कारण विशिष्ट रहा है। वीबी-जी रामजी बिल यदि अधिकार से हटकर मिशन मॉडल अपनाता है, तो भारत एक अलग वैश्विक प्रयोग की ओर बढ़ेगा, जिसकी सफलता या विफलता पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर रहेगी।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सुधार यापुनर्परिभाषा ?,वीबी-जी रामजी बिल निस्संदेह ग्रामीण रोजगार नीति में एक बड़ा बदलाव है। यह सवाल अभी खुला है कि क्या यह बदलाव ग्रामीण गरीबों के जीवन में वास्तविक सुधार लाएगा या यह केवल एक वैचारिक और प्रतीकात्मक पुनर्परिभाषा बनकर रह जाएगा।इसका उत्तर विधेयक के अंतिम स्वरूप, क्रियान्वयन की पारदर्शिता और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगा।

21 दिसंबर 2025 को मतगणना के दिन शराब बिक्री पर प्रतिबंध

पालघर(उत्तरशक्ति)। राज्य निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र द्वारा नगर परिषद/नगर पंचायत आम चुनाव 2025 की घोषणा के अनुसार पालघर जिले की पालघर, डहाणू और जव्हार नगर परिषद तथा वाडा नगर पंचायत के लिए मतदान मंगलवार 2 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ था। आयोग के निर्देशानुसार इन चुनावों की मतगणना रविवार, 21 दिसंबर 2025 को की जायेगी। मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से तथा सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने आदेश जारी करते हुए बताया कि महाराष्ट्र मद्य निषेध अधिनियम, 1949 तथा राज्य निर्वाचन आयोग के 4 नवंबर 2025 और 2 दिसंबर 2025 के आदेशों के तहत पालघर जिले की संबंधित नगर परिषदों एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में सभी प्रकार की आबकारी (शराब) अनुज्ञप्तियां बंद रहेंगी। जारी आदेश के अनुसार 21 दिसंबर 2025 को मतगणना की प्रक्रिया समाप्त होने तक पालघर नगर परिषद, डहाणू नगर परिषद, जव्हार नगर परिषद और वाडा नगर पंचायत की सीमाओं में शराब की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशित अवधि के दौरान यदि कोई अनुज्ञप्तिधारक शराब बिक्री करते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित नागरिकों एवं व्यापारियों से आदेशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।

बुकिंग शुरू होते ही टाटा सिएरा ने बाजार में मचाया तहलका

मुंबई। आइकॉनिक टाटा सिएरा ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में जोरदार वापसी धमाकेदार वापसी की है और कार प्रेमियों के दिलों पर छा गई है। बुकिंग शुरू होने के पहले ही दिन, ग्राहकों के उत्साह और भरोसे का नया कीर्तिमान रचते हुए सिएरा ने 70,000 से अधिक कन्फर्म ऑर्डर हासिल किए हैं। इसके अलावा, 1.35 लाख अन्य ग्राहकों ने अपनी पसंदीदा कॉन्फिगरेशन (फीचर्स/रंग) सबमिट कर दी है और वे बुकिंग की औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया में हैं। ग्राहकों का यह जबरदस्त रिस्पॉन्स साबित करता है कि टाटा सिएरा का 'आइकॉनिक स्टेटस' आज भी कायम है और एक प्रीमियम मिड-एसयूवी के तौर पर इसका जादू भारतीय ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बात करते हुए, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर, विवेक श्रीवास्तव ने कहा, हमें इतना शानदार रिस्पॉन्स देने के लिए हम अपने ग्राहकों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यह प्यार टाटा सिएरा के 'लीजेंडरी' स्टेटस पर एक बार फिर मुहर लगाता है। नए मानक तय करने की अपनी विरासत को कायम रखते हुए, सिएरा ने एक बिल्कुल नई कैटेगरी – 'प्रीमियम मिड-एसयूवी' – की शुरूआत की है। उन्होंने आगे कहा, ग्राहकों की बदलती उम्मीदों और सपनों को गहराई से समझते हुए, यह कार मिड-साइज एसयूवी की परिभाषा को एक बिल्कुल नए सिरे से लिखती है। स्पेस, कंफर्ट, लग्जरी, सुरक्षा और रोजमर्रा की उपयोगिता–हर पहलू को नया आयाम देते हुए, सिएरा इस सेगमेंट को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। सिएरा महज एक गाड़ी नहीं है; यह तरक्की, अपनी अलग पहचान और आकांक्षाओं का प्रतीक है। 25 नवंबर 2025 को टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स द्वारा लॉन्च की गई 'ऑल-न्यू टाटा सिएरा', एक ऐसे 'आइकॉन' का पुनर्जन्म है जिसने तीन दशकों से ज्यादा समय तक लोगों के सपनों, पहचान और यादों को संवारा है। नए दौर के लिए बड़ी बारीकी से तराशी गई सिएरा, अपनी शानदार विरासत और मूल 'डीएनए' को बरकरार रखते हुए, अत्याधुनिक मॉडर्निटी का बेहतरीन संगम है। यह कार उपलब्धि, व्यक्तित्व और 'कुछ नया खोजने के जज्बे' का एक दमदार प्रतीक है–जो साधारण से ऊपर उठने और संभावनाओं को नए सिरे से परिभाषित करने का आमंत्रण देती है।

साल के अंत में बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी से रहें सुरक्षित

मुंबई। त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में खरीदारी, यात्रा और आखिरी समय की तैयारियों की भागदौड़ बढ़ जाती है। इन सब जल्दबाजी के बीच हमारा ध्यान भी थोड़ा भटक जाता है, जिसका फायदा साइबर ठग उठाते हैं। नकली मैसेज, झूठे अलर्ट और लुभावने ऑफर भेजकर वे लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। फेडएक्स लोगों को सतर्क करते हुए आगाह करता है कि ऐसे फजी संदेशों और ईमेल्स से सावधान रहें, क्योंकि एक गलत क्लिक आपकी निजी या बैंक से जुड़ी जानकारी को खतरे में डाल सकता है। इसलिए क्लिक करने से पहले रुकें, सोचें और जांच करें। हॉलिडे स्कैम अक्सर ऐसे धोखाधड़ी वाले मैसेज के जरिये किए जाते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं। इनमें जाने-पहचाने ब्रांड के लोगो, सरल भाषा और मशहूर कंपनियों के नामों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग आसानी से भरोसा कर लें। FedEx लोगों को सतर्क करते हुए चेतावनी देता है कि ऐसे कई फर्जी संदेश खासतौर पर डिलीवरी से जुड़े होते हैं, जिनमें बताया जाता है कि कोई कूरियर देरी से है, उसे फ़्लैग कर दिया गया है या तुरंत पुष्टि की जरूरत है। ऐसे मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करने से व्यक्ति एक नकली वेबसाइट पर पहुँच सकता है, जिसे असली जैसा दिखाने के लिए डिजाइन किया गया होता है। इसके अलावा पैसे पाने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें जैसे कैशबैक ऑफर भी भेजे जाते हैं, जिनमें क्यूआर कोड स्कैन करते ही खाते से पैसे कट सकते हैं या यूजर को किसी फर्जी पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है।

लगातार थकान और हड्डियों का दर्द हो सकता है बोन मैरो कैंसर का संकेत

मुंबई/पटना। बोन मैरो कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जिसमें शरीर की स्वस्थ ब्लड सेल्स बनाने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। इसका सीधा असर ऑक्सीजन सप्लाई, इम्यूनिटी और ब्लड क्लॉटिंग पर पड़ता है। शुरूआती लक्षण जैसे बिना वजह थकान, बार-बार इन्फेक्शन या हड्डियों में दर्द अक्सर आम कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, जिससे बीमारी की पहचान देर से होती है। इसलिए अगर कोई लक्षण लंबे समय तक बना रहे, तो डॉक्टर से समय पर सलाह लेना बेहद जरूरी है। बोन मैरो कैंसर तब होता है जब बोन मैरो के अंदर असामान्य सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगते हैं और नॉर्मल ब्लड सेल्स के बनने की प्रक्रिया में रुकावट डालते हैं। इससे शरीर में खून की कमी, इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत में कमी और ब्लीडिंग कंट्रोल में परेशानी हो सकती है। कई मामलों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दर्द या फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है और शरीर के अन्य अंगों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है। चूंकि हर मरीज में बीमारी की गति और गंभीरता अलग हो सकती है, इसलिए इसकी सही मॉनिटरिंग और समय पर इलाज बहुत अहम होता है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साकेत के हीमैटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर, डॉ. रेयाज अहमद ने बताया कि बोन मैरो कैंसर के प्रमुख प्रकारों में ल्यूकेमिया, मल्टीपल मायलोमा और कुछ प्रकार के लिम्फोमा शामिल हैं।

केसीएन क्लब द्वारा विजय दिवस की 54वीं वर्षगाँठ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित

पालघर(उत्तरशक्ति/अजीत सिंह)। राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब (केसीएन क्लब) की सैनिक शाखा वेटरन्स भारत के तत्वावधान में 16 दिसम्बर विजय दिवस की 54वीं वर्षगाँठ के अवसर पर सातपाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता 1971 के युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी वयोवृद्ध पूर्व सैनिक अशोक दाजी मोरे ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ वीर नारी प्रतिभा प्रभाकर मोरे उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथियों में सातपाटी ग्राम पंचायत की सरपंच सीमा मिलिंद भोईर, उपसरपंच अभिजीत निशिकांत तरे, जिला परिषद पालघर के उमेद प्रभाग समन्वयक सुरेश छगन मावची, पूर्व ग्राम पंचायत सदस्या व केसीएन क्लब की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (महिला) नीता श्रीधर राऊत, वेटरन्स भारत के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व सैनिक एडवोकेट भाऊराव पुंडलिक तायड़े, केसीएन क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन मिश्र त्यागी, कोंकण मंडल अध्यक्ष राकेश आचार्य तथा निर्झरिणी प्रदेश अध्यक्ष कवि शेखर तिवारी प्रमुख रूप से शामिल रहे।

कार्यक्रम की शुरूआत मान्यवरों के हाथों दीप प्रज्वलन कर-के की गई। इसके पश्चात केसीएन क्लब द्वारा संचालित कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मंगला मन्डेकर, मनस्वी पाटील, मनीषा मेहेर, ईशा चौधरी, वैदेही पाटील, समीक्षा पागधरे, रुपाली भोईर, शलाका तरे, सुषमा म्हात्रे, वैशाली किणी, हर्षला पाटिल,

ज्योति पाटील, संजना वझे सहित अनेक प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र, सम्मान चिन्ह, शॉल, श्रीफल एवं तिरंगा अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

सरपंच सीमा भोईर ने अपने संबोधन में केसीएन क्लब के सामाजिक व राष्ट्रहित कार्यों की सराहना की। जिला परिषद के उमेद प्रतिनिधि ने संस्था के उन्नतिशील कार्यों को देखते हुए भविष्य में सरकारी सहयोग का आश्वासन दिया।

वहीं निर्झरिणी प्रदेश अध्यक्ष कवि शेखर तिवारी की देशभक्ति कविता ने उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया।

कार्यक्रम का सफल संचालन वेटरन्स भारत के राष्ट्रीय महासचिव भाऊराव पुंडलिक तायड़े ने किया। इस अवसर पर केसीएन क्लब प्रदेश उपाध्यक्ष संगीता जायसवाल, महासचिव जयंती महतो, युवा मोर्चा के डॉ. सत्येंद्र यादव, क्रिकेटर राकेश शर्मा, समाजसेवी अरविंद दुबे, व्यवसायी रवि महतो, जैतून सोलंकी, शोभा तिवारी, नितिन मन्डेकर, प्रसाद पागधरे, वैभव मोरे, भक्ति तांडेल, रुखसार पटेल, नुसरत सहित अनेक ग्राम पंचायत सदस्य, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन मिश्र त्यागी ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

भिवंडी में खरीदारी के बहाने ज्वेलर्स की दुकान पर आए युवक ने ढाई लाख का सोना लेकर फरार

आचार्य सूरजपाल यादव
भिवंडी (उत्तरशक्ति)। भिवंडी शहर के नारपोली गांव के भंडारी कंपाउंड स्थित श्री नागफणी ज्वेलर्स नामक दुकान पर खरीदारी के बहाने आए एक युवक ने वहां से सोने के झुमके वाली ट्रे लेकर भाग गया। बतादें कि यह घटना दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस के अनुसार बृजलाल जैन रात करीब नौ बजे अपनी ज्वेलर्स की दुकान में बैठे थे और झुमके खरीदने की बात कहकर अंदर आए युवक को दुकानदार बृजलाल जैन ने सोने के झुमके वाली ट्रे दिखाई और युवक ने देखते देखते जैसे ही दुकानदार का ध्यान भंग हुआ युवक ने सोने के झुमके वाली ट्रे उठाकर भाग खडा हुआ। सोने से भरा ट्रे लेकर भागते हुए युवक का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। चोरी हुये गहनों की कीमत 2 लाख 50 हजार 500 सौ रुपए बताई जा रही है। दुकानदार की शिकायत पर नारपोली पुलिस स्टेशन में अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

एक्सिस बैंक मीरा रोड में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया

मीरा भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा भायंदर में पुलिस आयुक्त ने पुलिस उपायुक्त (अपराध) संदीप डोइफोडे को निर्देश दिया है कि वे आम नागरिकों में साइबर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मीरा भायंदर वसई-विरार पुलिस आयुक्त कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। पुलिस आयुक्त की पहल पर, 5 दिसंबर 2025 को शाम 5.00 बजे से 6.00 बजे तक एक्सिस बैंक, शांति पार्क शाखा, मीरा रोड, मीरा रोड ईस्ट में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एक्सिस बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित 25-30 और 25-60 आयु वर्ग के

लोग उपस्थित थे।

साइबर पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक स्वप्निल वाव्हल ने साइबर से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान किया। वर्तमान में घटित हो रहे विभिन्न साइबर अपराध (ट्रेंडिंग साइबर अपराध)। सोशल मीडिया से संबंधित अपराध (सोशल मीडिया से संबंधित अपराध/सोशल मीडिया शिष्टाचार)। ऑनलाइन साइबर अपराधों से बचाव के तरीके (सावधानियां) के बारे में जानकारी। ऑनलाइन अपराध के शिकार होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करने के लिए कहां । शिकायत कहां और कैसे करें: इस कार्यक्रम में 25 से 60 वर्ष की आयु के कुल 25-30 बैंक अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की रूपरेखा बैंक के अध्यक्ष रसिक नरुल्ला ने प्रस्तुत की। कार्यक्रम में इंटरनेट के माध्यम से होने वाले वित्तीय लेन-देन में सुरक्षा बनाए रखने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया। सपोनी स्वप्निल वावल ने श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान किया, जिसमें धोखाधड़ी का शिकार हुए नागरिकों द्वारा बैंक से संपर्क करने पर आगे की कार्रवाई के बारे में मार्गदर्शन भी शामिल था। कार्यक्रम में उपस्थित श्रोताओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी और कार्यक्रम के बारे में सकारात्मक सुझाव भी दिए। बैंक के अध्यक्ष रसिक नरुल्ला ने उक्त कार्यक्रम के संबंध में साइबर मुद्दों पर उपयोगी जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सहायक पुलिस निरीक्षक स्वप्निल वावल को धन्यवाद दिया।

भिवंडी मनपा द्वारा बौद्धिक व लघु उद्योग ट्रेनिंग पंजीकरण में महिलाओं का दिखाया उत्साह

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। बौद्धिक व लघु उद्योग डेवलपमेंट एक्टिविटीज को लागू करने के लिए भिवंडी मनपा और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास सेंटर के बीच 3 दिसंबर को करारनामा एक साइन किया गया था जिसमें कम पढ़ी-लिखी महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए अलग-अलग कोर्स कराए जाएंगे। इसके लिए मनपा मुख्यालय में पंजीकरण चल रहा है जिसमें सैकड़ों महिलाएं पंजीकरण कराने आ रही हैं। महिलाओं के हित के लिए लघु उद्योग सक्षमीकरण पर फोकस इस पहल में फैशन, ज्वेलरी डिजाइन, ब्यूटी और ब्यूटी और वेलनेस सर्विसेज, फूड प्रोसेसिंग और

पाकशाला से जुड़े प्रोडक्ट्स, हाथ से बने साबुन, मोमबत्तियां, नैपकिन, बुके और एरोमा प्रोडक्ट्स, पावरलूम इंडस्ट्री-बेस्ड स्किल डेवलपमेंट, और लाजिस्टिक्स आपरेशन और डेटा एंट्री की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए पिछले सप्ताह मनपा मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर महिलाओं के लिए गाइडेंस और रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। एक सप्ताह के दौरान 250 से ज्यादा महिलाओं ने पंजीकरण करके इस पहल में उत्साह दिखाया है। इन पंजीकृत महिलाओं को भिवंडी शहर में ही ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें नौकरी और स्वरोजगार दिया जाएगा।

8 वें मूनव्हाइट फिल्म्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड फंक्शन में हुए पद्मश्री अनूप जलोटा शामिल

कार्यक्रम में धर्मेंद्र, मनोज कुमार, असरानी, मधुमति, पंकज धीर, सतीश शाह जैसी हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई

मुंबई (उत्तरशक्ति)। मुम्बई में आयोजित 8वें मूनव्हाइट फिल्म्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MWFIFF 2025 के पुरुस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भजन सम्राट अनूप जलोटा सहित कई हस्तियां शामिल हुईं। सभी ने आयोजक देवाशीष सरगम राज को बधाई और शुभकामनाएं दीं। अनूप जलोटा ने सभी पुरस्कार विजेताओं को अपनी ओर से बधाई दी। पंडित सुवाषित राज, को- फाउंडर शिप्रा राज, गायक सुहर्ष राज, गायिका दिलराज कौर, संगीतकार विवेक प्रकाश ने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई. मुम्बई के मुक्ति ऑडिटोरियम में भव्य रूप से आयोजित इस कार्यक्रम को अनूप जलोटा ने प्रेजेंट किया.

कार्यक्रम में धर्मेंद्र, मनोज कुमार, असरानी, मधुमति, पंकज धीर, सतीश शाह जैसी हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. गायक संजय शांगलु ने अपनी प्रस्तुति दी। जमसाज बैंड ने तेरी दीवानी जैसे गीतों की परफॉर्मेंस देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

देवाशीष सरगम (राज) ने फिल्म फेस्टिवल में एक फिल्म बतौर डायरेक्टर साइन की है. साउथ के निमार्ता और ऐक्टर आनंद नायडू की एक फिल्म वह डायरेक्ट करने जा रहे हैं.

रूस के फि ल्मकार एवगेनी श्मेलेव (Evgeny shmelev) की यहां विशेष उपस्थिति रही जिन्हें सम्मानित किया गया. यहां जिन फि ल्मों को अवॉर्ड से नवाजा गया उनमे उल्लेखनीय है स्ट्रैंडेड पर्ल (फीचर फिल्म न्यूजीलैंड), नानक चिंता मत करो - शॉर्ट फिल्म भारत, खोज - रीजनल शॉर्ट फिल्म - भारत, जूल्स - इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म अमेरीका, मैरियोनेट म्यूज़िक वीडियो पॉप RNB अमेरीका, द फैमिली फोटो - इंटरनेशनल एनीमेशन शॉर्ट फिल्म अमेरिका.

इस अवसर पर गायक सुहर्ष राज ने अपने लोकप्रिय म्युजिक वीडियो ₹काफिर दीवाना₹ की कुछ लाइन गाकर समा बांध दिया. जूरी मेंबर्स में अनूप जलोटा, जसपिंदर नरुला, दिलराज कौर, पंडित सुवाषित राज का नाम उल्लेखनीय है.

जिले में घरकुल लाभार्थी संवाद अभियान -चरण 3 एवं गृहप्रवेश कार्यक्रम का होगा आयोजन

पालघर(उत्तरशक्ति)। मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान के अंतर्गत पालघर जिले में दिनांक 23 एवं 24 दिसंबर 2025 को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में एक साथ ह्ल घरकुल लाभार्थी संवाद अभियान झ्र चरण 3 ह्व तथा पूर्ण हुए घरों का गृहप्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इसी अवधि में महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों की प्रभात फेरी, जनजागरण अभियान तथा महिलाओं की हीमोग्लोबिन जांच भी की जायेगी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना झ्र ग्रामीण (ढटअ -ॠ) चरण 2 के तहत पालघर जिले को 60,574 घरों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें 100 प्रतिशत लाभार्थियों को मंजूरी दी जा चुकी है। इसी तरह प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत 10,478 घरों के लक्ष्य को भी शत-प्रतिशत मंजूरी प्रदान की गई है। हालांकि चरण 2 के अंतर्गत 13,861 तथा अंतर्गत 3,322, कुल मिलाकर 17,183 लाभार्थियों को प्रथम किश्त मिलने के बावजूद अब तक घरकुल निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस पृष्ठभूमि में घरकुल लाभार्थी संवाद अभियान झ्र चरण 3 के माध्यम से इन सभी लाभार्थियों तक प्रत्यक्ष पहुंच बनाकर संवाद किया जायेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों से सीधे संपर्क कर उनकी समस्याओं और अड़चनों को समझना, उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना, घर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के लिए प्रेरित करना तथा समय-सीमा में घर पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहित करना है। इसी दौरान पूर्ण हुए घरों का गृहप्रवेश कार्यक्रम भी आयोजित किया जायेगा।

चरण 2 के अंतर्गत 18,972 तथा के अंतर्गत 2,923, कुल 21,895 घर पूर्ण हो चुके हैं। इन घरों का गृहप्रवेश कार्यक्रम गट विकास अधिकारी, ग्रामसेवक एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों के माध्यम से नियोजित रूप से संपन्न किया जायेगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान के तहत उमेद योजना के माध्यम से पात्र महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण वितरण, बचत समूहों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने।

डब्बा नेटवर्क ने पीएम-वाणी रोलआउट को दी रफ्तार

बेंगलुरु/मुंबई (उत्तरशक्ति)। जैसे-जैसे भारत में डिजिटल अपनाने की रफ्तार तेज हो रही है–वढक भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीहेल्थ और बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ–मजबूत, भरोसेमंद और समावेशी इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इस राष्ट्रीय प्राथमिकता को साकार करने की दिशा में डब्बा नेटवर्क, एक कम्युनिटी-पावर्ड ब्रॉडबैंड मार्केटप्लेस, भारत सरकार की पीएम-वाणी (प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) पहल के सबसे सफल कार्यान्वयनकताओं में से एक के रूप में उभरा है। विकेंद्रीकृत, समुदाय-आधारित तैनाती और एक टिकाऊ वित्तीय मॉडल के जरिये डब्बा नेटवर्क सार्वभौमिक और किफायती इंटरनेट के विजन को जमीनी हकीकत में बदल रहा है, और भारत को एक अरब से अधिक लोगों को ऑनलाइन लाने के दीर्घकालिक लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। पिछले एक वर्ष में, डब्बा नेटवर्क ने कम सेवा-प्राप्त और उच्च मांग वाले

क्षेत्रों में तेजी से ऑन-ग्राउंड क्रियान्वयन का प्रदर्शन किया है। स्थानीय उद्यमियों और कम्युनिटी पार्टनर्स के माध्यम से कंपनी ने 73,128 सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट तैनात किए हैं।

2020 में शुरू की गई पीएम-वाणी पहल ने सार्वजनिक वाई-फाई तैनाती को तेज करने और स्थानीय उद्यमियों, छोटे आईएसपी, हॉटस्पॉट प्रदाताओं और कम्युनिटी नेटवर्क्स को सशक्त बनाने के लिए खुले और इंटरऑपरेबल डिजिटल ढांचे की स्थापना की। जहां पीएम-वाणी ने राष्ट्रीय स्तर पर ब्लूप्रिंट तैयार किया, वहीं डब्बा नेटवर्क ने पिछले आठ वर्षों में इस आर्किटेक्चर को एक कार्यशील और स्केलेबल मॉडल में बदलने का काम किया है–खासकर उन क्षेत्रों में, जहां पारंपरिक टेलीकॉम मॉडल के तहत अंतिम मील ब्रॉडबैंड आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं रहा है।

डब्बा नेटवर्क के सीईओ और संस्थापक करम लक्ष्मण ने कहा, भारत की कनेक्टिविटी चुनौती ही उसकी सबसे बड़ी अवसर है। ब्रॉडबैंड की मांग सार्वभौमिक है, लेकिन पारंपरिक तैनाती मॉडल अंतिम मील के लिए आर्थिक रूप से उपयुक्त नहीं हैं। पीएम-वाणी इस सोच को बदलता है और स्थानीय उद्यमियों व कम्युनिटी पार्टनर्स को वहां इंटरनेट बनाने के लिए सशक्त करता है जहां इसकी सबसे अधिक जरूरत है।

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालय :
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामीः शरद फागूराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * **संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति,** समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालयः मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, **मो.- 9554493941** email ID- uttarshaktinews@gmail.com

ट्रेन से कटकर साइकिल सवार की दर्दनाक मौत

घटनास्थल पर उमड़ी भीड़, पुलिस ने कब्जे में लिया शव

आजमगढ़ (उत्तरशक्ति)। जिले के निजामाबाद तहसील क्षेत्र में सरायमीर रेलवे स्टेशन के पास बुधवार सुबह करीब 10 बजे एक साइकिल सवार की रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान देवेश कुमार (पुत्र बहादुर) निवासी कोल्ह, कोतवाली फूलपुर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, आसनसोल-गोंडा एक्सप्रेस ट्रेन ने सरायमीर रेलवे क्रासिंग पर देवेश कुमार को काट दिया। घटना आउटर सिग्नल के अंदर हुई, जो जीआरपी (गवर्नमेंट रेलवे पुलिस) के क्षेत्राधिकार में आता है। घटना की सूचना मिलते ही सरायमीर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। चूंकि यह क्षेत्र

जीआरपी आजमगढ़ के अंतर्गत आता है, इसलिए सरायमीर पुलिस ने जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी की टीम ने मौका-मुआयना किया, शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि देवेश कुमार साइकिल से घटनास्थल पहुंचे थे और साइकिल को ट्रैक के किनारे खड़ा करके ट्रैक पर लेट गए, जिससे यह आत्महत्या की घटना प्रतीत होती है। हालांकि पुलिस इसकी आधिकारिक जांच कर रही है। घटना के बाद सरायमीर रेलवे क्रासिंग पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

युवती को बातों में बहला फुसला कर 4.90 लाख की ठगी

व्हाट्सएप लिंक के जरिए ठगों ने युवती को बनाया अपना शिकार

आजमगढ़ (उत्तरशक्ति)। जनपद आजमगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र से साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है। आसिफगंज पुरानी कोतवाली निवासी प्रदीप नारायण सिंह ने थाना कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि अज्ञात साइबर ठगों ने उनकी पुत्री श्रुति सिंह को व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से गुमराह कर लाखों रुपये की ठगी कर ली। प्रार्थी के अनुसार उनकी पुत्री के मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप लिंक आया, जिस पर बातचीत के दौरान ठगों ने उसका ब्रेनवॉश कर लिया। इसके बाद उनकी पुत्री से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा स्थित खाते से अलग-अलग नामों पर कुल 4 लाख 49 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए। इसके अलावा कुछ धनराशि बैंक ऑफ बड़ौदा यूपी चौक स्थित खाते से भी ट्रांसफर कराई गई। इस तरह से कुल 490000 की ठगी की गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि ठगों ने योजनाबद्ध तरीके से युवती को भ्रमित कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इस बाबत अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और साइबर सेल की मदद से ठगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात लिंक, कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें और सतर्क रहें।

चाइनीज मांझा के प्रति जारी रहेगा जागरूकता अभियानः उषा जायसवाल

विसर्जन घाट पर कार्यक्रम करके सपा नेत्री ने लोगों को किया जागरूक

मांझा बेचने एवं उपयोग करने वालों के खिलाफ हो दण्डात्मक कार्यवाही

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। चाइनीज मांझा के प्रति लोगों को जागरूक करते हुये समाजवादी महिला सभा की प्रदेश सचिव उषा जायसवाल का जागरूकता अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में नगर के मोहल्ला नखास के सद्भावना पुल के नीचे स्थित नवदुर्गा शिव मन्दिर के पास विसर्जन घाट पर लोगों से अपील किया कि चाइनीज मांझा जो मौत का मांझा बन चुका है, को रोका जाना आवश्यक हो गया। हम सभी अभिभावक अपने बच्चों सहित अगल-बगल मोहल्लों में चाइनीज मांझे का उपयोग कर रहे लोगों को इसके दुष्परिणाम के प्रति समझाकर इसके प्रयोग को रोका जा सकता है। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद महिलाओं, बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों आदि से श्रीमती जायसवाल ने लाउडस्पीकर के माध्यम से घूम-घूम करके जागरूक करने का काम किया। वहीं जिला एवं पुलिस प्रशासन के लोगों से भी अपील किया कि चाइनीज मांझा बेचते हुये कोई भी दुकानदार पाया जाय तो उसके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाय। उन्होंने बताया कि चाइनीज मांझा का शिकार 40 वर्षीय संदीप तिवारी जो प्राइवेट शिक्षक थे, हो चुके हैं। अब उनके परिवार को चलाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में परिवार के समक्ष मानो वज्रपात हो गया है। इस दौरान मृतक संदीप तिवारी को श्रद्धांजलि देते हुये सपा नेत्री ने कहा कि उनकी शहादत बेकार नहीं जायेगी। हम सभी लोग टीम बनाकर घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। साथ ही जिला एवं पुलिस प्रशासन यदि नहीं चेता तो उसका भी घेराव किया जायेगा। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सुशील दुबे, सदर विधानसभा अध्यक्ष महिला सभा सुशीला यादव, महासचिव पूनम यादव, कोषाध्यक्ष पिंकी गुप्ता, राधिका यादव, रेखा सिंह, धर्मेन्द्र चौरसिया, शिल्पा जायसवाल, शाहिद सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

नौचंदी के पोस्टर से छेड़छाड़ पर मचा बवाल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जनपद के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरा पट्टी गांव में उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब शिया समुदाय की ओर से इमामबाड़ा पर लगाए गए नौचंदी के पोस्टर के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक हरकत किए जाने की सूचना सामने आई। आरोप है कि किसी अराजकतत्व द्वारा पोस्टर पर थूक दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया।

घटना की जानकारी मिलते ही शिया समुदाय के लोग मौके पर जुट गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। देखते ही देखते मामला बढ़ता नजर आया, लेकिन सूचना पर पहुंची सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को संभाला। पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया, जिससे हालात पर काबू पाया जा सका।

पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी थाना प्रभारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और तहरीर मिलने के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इक्कीसवीं सदी में भारतीय युवाओं के लिए वैश्विक अवसरों की भरमारः डॉ.शक्ति सिंह

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) भौतिकीय विज्ञान अध्ययन एवं शोध संस्थान के रसायन विज्ञान विभाग एवं केमिकल कम्युनिकेशन सोसाइटी के द्वारा उच्च शिक्षा में वैश्विक अवसर विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। व्याख्यान के मुख्य वक्ता फोंटेरा कोऑपरेटिव लिमिटेड, न्यूजीलैंड के प्रॉडक्ट इंटीग्रेशन मैनेजर डॉ. शक्ति सिंह ने कहा कि इक्कीसवीं सदी में भारत के युवाओं के लिए दुनिया भर में अवसर की भरमार है। आज वैश्विक स्तर पर चिकित्सा, कृषि, फार्मा उद्योग आदि के क्षेत्र में नई संभावनाएं उभरी है। डॉ. सिंह ने विद्यार्थियों को फार्मा उद्योग में

उपलब्ध अवसर एवं चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

अध्यक्षीय संबोधन में निदेशक प्रो. प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को गहराई से समझ कर उसमें काम करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ.प्रमोद कुमार ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार के अधिकतम अवसर प्राप्त हो, इसके लिए विभाग लगातार व्याख्यान एवं प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है।

कार्यक्रम का संचालन केमिकल कम्युनिकेशन सोसाइटी के आकाश यादव तथा धन्यवाद ज्ञापन आशिया फातमा ने किया। इस अवसर पर डॉ. नितेश जायसवाल, डॉ. अजीत सिंह, डॉ. मिथिलेश यादव, डॉ. दिनेश वर्मा एवं सभी छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

सार्वजनिक भूमि पर कब्जा जारी, भूमाफियाओं का हौसला बुलंद

लम्बे समय से जमें एक चर्चित राजस्व कर्मी के चलते उक्त कार्य को मिल रहा है बढ़ावा

केराकत, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। प्रदेश सरकार की योगी आदित्यनाथ सरकार जहाँ पूरे प्रदेश में भू माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन मुक्त करानें का सघन अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराये जानें का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं स्थानीय नगर पंचायत क्षेत्र के मुहल्ला सिपाह में स्थित सरकारी नाले की जमीन पर कुछ दबंग किस्म के लोगों द्वारा अतिक्रमण कर अपना कब्जा जमाया जा रहा है। यहीं तक उक्त दबंगों द्वारा उसके आस पास लगे हुऐ पेड़ों बांस आदि को

मनमानी ढ़ंग से काटकर उठाले जा रहे हैं। और कहते हैं कि जमीन और पेड़ मेरा है और यह मेरे दादा बाबा का जब कि राजस्व अभिलेखों में कहीं भी उपरोक्त दबंगों का नामों निशान तक नहीं दर्ज है। सूत्र बताते हैं कि लम्बे समय से जमें एक राजस्व कर्मी की पर्दे के पीछे से मिली भगत के चलते उक्त कार्य को बढ़ावा मिल रहा है। अपनें कार्यों को लेकर हमेशा चर्चित और विवादों में बनें रहनें वाले राजस्व कर्मी इसके पूर्व भी नगर क्षेत्र के भूमि सम्बन्धित की मामलों को लेकर काफी चचाओं में बनें रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि उच्चाधिकारियों की जब तक मुझपर कृपा दृष्टि बनी रहेगी मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पायेगा। बहुत करेंगे तो मेरा ट्रान्सफर करा देंगे। जबकि बताया जाता है कि उक्त नाले के प्रकरण को लेकर प्रदेश सरकार के मुखिया से मिलकर उन्हें पूरी वस्तु स्थिति से अवगत भी कराया जायेगा।

डॉ.अंजना सिंह को श्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महिला विंग राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर दी बधाई

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिले की डॉ. अंजना सिंह को श्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महिला विंग राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर मंगलवार को जलालपुर क्षेत्र के त्रिलोचन महादेव बाजार निवासी फिल्म अभिनेता/समाजसेवी चन्दन सेठ के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने डॉ.अंजना सिंह के जौनपुर

निवास स्थान पर पुष्प गुच्छ व अंगवस्त्रम् देकर बधाई व स्वागत किया गया।उन्होंने महासभा को मजबूती के लिए समाज के लोगों से संपर्क करने के साथ ही सहयोग करने की बात कही।युवाओं की ओर से पुष्पमालाओं से किए गए स्वागत को लेकर अभिनेता चन्दन सेठ ने उनका उत्साहवर्धन किया और महासभा को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर दिनेशचन्द्र श्रीवास्तव (प्रबंधक न्यु लार्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल), डॉ. सुदर्शन मिश्रा, अभिषेक अग्रहरी (बीरू), अमन सिंह, मो.आजाद, निलेश सिंह, सर्वेश सिंह, राज यादव सहित जिले के तमाम-लोगों का बधाई एवं शुभकामनाएं देने के लिए तांता लगा रहा। सादर आभार रमेश सिंह (राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिन्दू भगवा वाहिनी) ने किया।

तेजस्वी किसान मार्ट का 9वाँ स्टोर उद्घाटित

करमा,सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। जनपद में स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में तेजस्वी किसान मार्ट के 9वें स्टोर का शुभारंभ माननीय डॉ० अनिल मौर्य जी, विधायक द्वारा फीता काटकर किया गया। स्टोर का संचालन लक्ष्मी गणेश आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा, जिसमें सरंगा क्लस्टर की प्रमुख सहभागिता रही।

कार्यक्रम में उपायुक्त स्व-रोजगार श्रीमती सरिता सिंह, जिला मिशन प्रबंधक श्री एम० रवि, सहायक विकास अधिकारी इम्तियाज आलम, आईएसबी अडीओ महेंद्र सिंह, ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई करमा से जगदीश चंद्र रजक, प्रदीप कुमार, शिवकुमार उजागर उपस्थित रहे।

पशुपालन विभाग से मुख्य जिला पशु चिकित्साधिकारी डॉ० अजय कुमार मिश्रा, अपर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ० राधे श्याम गुप्ता, डॉ० आनंद कुमार, डॉ० राधेश्याम तथा कृषि, ग्राम विकास व बैंकिंग विभाग से कल्पनाथ मौर्य, ऋषि कुमार, छोटेलाल यादव, नाश कुमार, यूपी ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधक ओम प्रकाश गौंड मौजूद रहे।

साथ ही गोपाल सिंह वैद्य, ई० प्रकाश पाण्डेय, संजय सिंह, संतोष कुमार पटेल, श्याम नारायण पटेल, लालजी तिवारी, सुरेंद्र मौर्य, मनीष पटेल, राहुल पटेल, कृष्णा पटेल, वीरू पटेल, गोपाल जी सहित अनेक गणमान्य नागरिक व समूह सखियाँ उपस्थित रहीं। वक्ताओं ने कहा कि तेजस्वी किसान मार्ट के माध्यम से अब उत्पादक से उपभोक्ता तक का सीधा सफर स्वयं सहायता समूहों के लिए भी साकार हो रहा है, जो महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

पीयू में एलिवस लाइफ साइंस का कैंपस साक्षात्कार 18 को

छात्रों के लिए विस्तृत मार्गदर्शन एवं पूर्व-तैयारी सत्र आयोजित

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के केंद्रीय प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ द्वारा एलिवस लाइफ साइंस के सहयोग से 18 दिसंबर को विश्वविद्यालय परिसर में एम.एससी. एवं बी.एससी. रसायन विज्ञान तथा एम.एससी. एवं बी.एससी. सूक्ष्म जीवविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कैंपस साक्षात्कार/प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। यह आयोजन विद्यार्थियों को उद्योग से सीधे जोड़ने तथा उन्हें रोजगार के वास्तविक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। कैंपस साक्षात्कार से पूर्व विद्यार्थियों को चयन प्रक्रिया के लिए सक्षम बनाने हेतु केंद्रीय प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. प्रदीप कुमार द्वारा एक विशेष मार्गदर्शन एवं ओरिएंटेशन सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में प्रो. कुमार ने एलिवस लाइफ साइंस की कार्यप्रणाली, चयन प्रक्रिया, लिखित/तकनीकी परीक्षण, एचआर इंटरव्यू, आवश्यक दस्तावेजों की सूची, रिज्यूमे प्रस्तुतीकरण, संप्रेषण कौशल तथा साक्षात्कार में आत्मविश्वास बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। प्रो.कुमार ने विद्यार्थियों को बताया कि साक्षात्कार के दौरान विषय-विशेष की बुनियादी अवधारणाओं की स्पष्ट समझ, व्यावहारिक ज्ञान, सकारात्मक दृष्टिकोण और पेशेवर आचरण का विशेष महत्व होता है। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया कि उद्योग जगत केवल अकादमिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि समस्या-समाधान क्षमता, टीमवर्क और प्रभावी संवाद कौशल की भी अपेक्षा करता है। सत्र के दौरान विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए अनेक प्रश्नों का प्रो. कुमार ने सरल एवं व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समाधान किया, जिससे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ा और वे चयन प्रक्रिया के प्रति अधिक सजग एवं तैयार महसूस करते दिखे।

इस अवसर पर डॉ. नितेश जायसवाल, डॉ. संदीप वर्मा सहित विभिन्न विभागों के शिक्षकगण उपस्थित रहे। सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों को इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया तथा समयबद्ध तैयारी, अनुशासन और व्यवस्थित योजना के महत्व पर बल दिया। विद्यार्थियों में इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। केंद्रीय प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ की यह पहल विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट संस्कृति को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों के करियर निर्माण में एक प्रभावी कदम के रूप में देखी जा रही है।

दो दिवसीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ

जिला स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। 47वीं जिला स्तरीय दो दिवसीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह-2025 का आयोजन बी.आर.पी. इंटर कॉलेज के खेल मैदान में भव्य एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया।

प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर से चयनित होकर आई तहसील स्तरीय टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण, उत्तर प्रदे गिरीश चन्द्र यादव तथा सदस्य विधान परिषद बृजेश सिंह प्रिंसू. द्वारा विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र, पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ एवं एडी बेसिक शिक्षा विभाग हेमंत राव की गरिमामयी उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर एवं माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल द्वारा अतिथियों का बुके भेंट कर स्वागत किया गया तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने गुब्बारे उड़ाकर एवं दौड़ प्रतियोगिता में क्लैपर बजाकर खेल प्रतियोगिताओं की औपचारिक शुरूआत की। इस अवसर पर तहसील स्तर से प्रस्तुत मार्च-पास्ट दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहा। बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु आतिशबाजी भी की गई।

मुख्य अतिथि राज्यमंत्री ने अपने संबोधन में सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं जनपद में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग बच्चों को खेलकूद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा

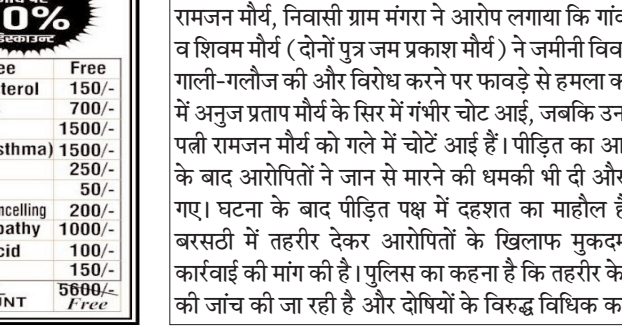

है। खेल बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए प्रत्येक बच्चे को किसी न किसी खेल से अवश्य जुड़ना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छा प्रयास करने के बावजूद स्थान प्राप्त न करने वाले खिलाड़ियों को निराश नहीं होना चाहिए तथा खेल को सदैव खेल भावना से खेलना चाहिए।

सदस्य विधान परिषद बृजेश सिंह प्रिंसू. ने प्रतियोगिता के उत्कृष्ट आयोजन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उनकी टीम एवं शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि टीम भावना से ही हर कार्य बेहतर रूप लेता है।

जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों के शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा प्रदर्शित होती है, जिससे वे आने वाले समय में विकसित भारत, विकसित उ0प्र0 और विकसित जौनपुर की संकल्पना को साकार करेंगे। सभी बच्चों को प्रात्साहित करते हुए कहा कि सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहना आवश्यक है और सतत प्रयास से सफलता प्राप्त होती है।

जिलाधिकारी ने इस तरह के भव्य एंव दिव्य कार्यक्रम आयोजित करने पर बेसिक शिक्षाअधिकारी और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे सभी के कार्यो की प्रशंसा की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल ने कहा कि बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने, उन्हें उचित मंच प्रदान करने तथा उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है।

प्रतियोगिता के अंतर्गत जूनियर बालिका वर्ग 600 मीटर दौड़ में रामनगर ब्लॉक की बिन्दु पटेल ने प्रथम, करंजाकला ब्लॉक की शिवांगी ने द्वितीय तथा मुफ्तीगंज की अलका यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं जूनियर बालक वर्ग 600 मीटर दौड़ में मुफ्तीगंज के आदित्य वर्मा प्रथम, महाराजगंज के अमन निषाद द्वितीय एवं सिकरारा ब्लॉक के आर्यन यादव तृतीय स्थान पर रहे। विजेता खिलाड़ियों को माननीय मंत्री जी एवं जिलाधिकारी द्वारा मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन खण्ड शिक्षा अधिकारी रमेश चन्द्र पटेल एवं नुपुर श्रीवास्तव द्वारा किया गया।

इस अवसर पर बी.आर.पी. इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. प्रमोद श्रीवास्तव, समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, विभिन्न बेसिक शिक्षक संघों के अध्यक्ष/पदाधिकारी, ए.आर.पी. शिक्षकगण सहित बड़ी संख्या में शिक्षक एवं खेल शिक्षक उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में जिला एवं ब्लॉक स्तरीय स्पोर्ट्स शिक्षकों का विशेष योगदान रहा।

जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने किया जिला कारागार का त्रैमासिक निरीक्षण

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार शशि, जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ के द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारागार में निरुद्ध कैदियों से संवाद करते हुए उनकी विधिक आवश्यकताओं, ठंड से बचाव की व्यवस्थाओं तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी।

कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सा सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही कारागार में साफ-सफाई, भोजन की गुणवत्ता, पेयजल, तथा सुरक्षा संबंधी प्रबंधों का भी अवलोकन किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक शहरी आयुष श्रीवास्तव, जेल अधीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

शिफा मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल
मानीकलॉ, जौनपुर
निःशुल्क मेगा कैम्प
(डायबटीज एवं हड्डी रोग)
23 दिसम्बर 2025, दिन मंगलवार, प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक
Dr. MOHD CHAND BAGWAN
MBBS, DNB (MD)
PDCC-CRITICAL CARE MEDICINE
CCEBDM (DIABETES)
डायबटीज, चेस्ट एवं हृदय रोग विशेषज्ञ
Dr. ABU FAISAL
MBBS, D. Ortho (Lko), DNB (Ortho)
PGDS (Orthopedic) Surgeon
गोल्ड मेडलिस्ट
(हड्डी, जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ)
मो0 नं0 7380850571 पर सम्पर्क कर एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन करायें और इस अवसर का लाभ उठाएं।
डा0 मोहम्मद अकमल
(डायरेक्टर)
शिफा हास्पिटल, मानीकलॉ, जौनपुर-9451610571
अन्य ब्लड जाँच पर 50% डिस्काउन्ट
OPD Fee Free
Cholesterol 150/-
HbA1C 700/-
BMD 1500/-
PFT(Asthma) 1500/-
TSH 250/-
Sugar 50/-
Diet Councelling 200/-
Neuropathy 1000/-
Uric Acid 100/-
RA 150/-
TOTAL AMOUNT 5600/- Free

जमीन विवाद में युवक व उसकी मां से मारपीट, फावड़े से हमला; जान से मारने की धमकी

दिनेश विश्वकर्मा

बरसठी,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। थाना बरसठी क्षेत्र के ग्राम मंगरा में जमीन विवाद को लेकर दबंगों द्वारा युवक व उसकी मां से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर के अनुसार घटना दिनांक 15 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 9 बजे की है। पीड़ित अनुज प्रताप मौर्य पुत्र रामजन मौर्य, निवासी ग्राम मंगरा ने आरोप लगाया कि गांव के ही शुभम मौर्य व शिवम मौर्य (दोनों पुत्र जम प्रकाश मौर्य) ने जमीनी विवाद को लेकर पहले गाली-गलौज की और विरोध करने पर फावड़े से हमला कर दिया। इस हमले में अनुज प्रताप मौर्य के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि उनकी माता मंजू लता पत्नी रामजन मौर्य को गले में चोटें आई हैं। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपितों ने जान से मारने की धमकी भी दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित पक्ष में दहशत का माहौल है। पीड़ित ने थाना बरसठी में तहरीर देकर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे फ्लाईओवर को मिली मंजूरी, वसई-विरार को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत, राजन नाईक की कोशिशें रंग लाईं

वसई रोड। वसई-विरार क्षेत्र के लिए बड़ी राहत की खबर है। एमएमआरडीए के 563 करोड़ 48 लाख रुपये के फंड को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। यह राशि विराटनगर और ओसवालनगर में बनने वाले रेलवे फ्लाईओवर के लिए स्वीकृत की गई है, जिससे क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही ट्रैफिक समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। इन फ्लाईओवर परियोजनाओं के लिए भाजपा विधायक राजन नाईक लगातार एमएमआरडीए के साथ फॉलोअप कर रहे थे। उनकी निरंतर कोशिशों के चलते यह महत्वपूर्ण मंजूरी संभव हो सकी। वसई-विरार शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए नायगांव और वसई रोड रेलवे स्टेशन के बीच उमेलमान, वसई रोड और नालासोपारा के बीच अलकापुरी, नालासोपारा और विरार के बीच ओसवालनगर तथा विराटनगर में रेलवे लाइन पर फ्लाईओवर बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इन सभी परियोजनाओं को वेस्टर्न रेलवे से भी सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है।

वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्र में प्रस्तावित चार रेलवे फ्लाईओवर में से विराटनगर और ओसवालनगर के लिए जमीन उपलब्धता का गारंटी लेटर पहले ही दिया जा चुका था। वहीं, अलकापुरी और उमेलमान फ्लाईओवर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया निजी, सरकारी और नमक के खेतों से जुड़ी होने के कारण पूरी नहीं हो सकी थी। इसी पृष्ठभूमि में, जमीन उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एमएमआरडीएआयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी ने विराटनगर और ओसवालनगर फ्लाईओवर के लिए 563.48 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपा था, जिसे अब प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। इस फैसले के लिए विधायक राजन नाईक ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही नालासोपारा हाईवे से नालासोपारा रेलवे स्टेशन तथा विरार हाईवे से विरार रेलवे स्टेशन तक सड़कों के कंक्रीटीकरण के लिए सीमांकन कार्य शुरू हो चुका है। विधायक राजन नाईक ने भरोसा जताया है कि इन कार्यों को भी जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी।

पीएम किसान योजना के लि फार्मर आईडी अपडेट अनिवा

सिवान (उत्तरशक्ति)। महाराजगंज बिहार के सिवान जिला अंतर्गत महाराजगंज प्रखंड के विभिन्न गांवों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों का फार्मर आईडी अपडेट करने का कार्य तेजी से चल रहा है। किसानों की भूमि संबंधी जानकारी का सत्यापन कर फार्मर आईडी बनाई जा रही है। विभागीय निर्देश के अनुसार बिना फार्मर आईडी के अब किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। समय पर आईडी अपडेट नहीं कराने वाले किसानों का नाम लाभुक सूची से हटाया जा सकता है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि योजना का लाभ जारी रखने के लिए सभी किसानों का फार्मर बनाना अनिवार्य है। इसके लिए किसान अपने क्षेत्र के हल्का कर्मचारी या सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं। यह प्रक्रिया कृषि ए सुधार विभाग के संयुक्त से की जा रही है, वास्तविक किसानों व योजनाओं का लाभ मिलेगा ऐसा किसान आवश्यक दस्तावेजों के जल्द फार्मर आईडी की अपील की है। उन्होंने पराली न जलाने का आग्रह करते हुए कहा कि पर्यावरण प्रदूषित होता मिट्टी की उर्वरता घट जाती है किसानों से पराली वैकल्पिक उपयोग कर अपील की गई है।

कल्याण में हुई घटना पर रैपिडो अधिकारी का बयान

मुंबई। हम कल्याण में हुई इस बेहद परेशान करने वाली घटना से अवगत हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा–इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आरोप बहुत गंभीर हैं, और इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएँ पीड़िता और उनके परिवार के साथ हैं। हम यह साफ करना चाहते हैं कि आरोपी व्यक्ति रैपिडो कैप्टन नहीं है और कभी भी नहीं रहा। शुरूआती रिपोर्टों में उसका नाम गलती से रैपिडो से जोड़ा गया था। उसने रैपिडो से जुड़ने के लिए आवेदन जरूर किया था, लेकिन हमारी सख्त जांच प्रक्रिया में वह पास नहीं हुआ, इसलिए उसका ऑनबोर्डिंग तुरंत ही रोक दिया गया। अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि शिकायतकर्ती ने 13 दिसंबर 2025 को किसी अन्य प्लेटफॉर्म से बाइक टैक्सी बुक की थी।

रैपिडो हमेशा कानून का पालन करते हुए सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। हमारे सभी कैप्टन की पूरी पृष्ठभूमि जांच, केवाईसी सत्यापन, और व्यवहार व सुरक्षा से जुड़े प्रशिक्षण अनिवार्य होते हैं। किसी भी विश्वसनीय शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं–जैसे रात 10 बजे के बाद महिला यात्रियों के लिए सेफ़्टी चेक-इन, 247 इन-ऐप रडर सपोर्ट, और हर यात्रा से पहले कैप्टन और वाहन की जानकारी की पुष्टि करने के लिए नियमित रिमाइंडर। यात्रियों की सुरक्षा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम एक बार फिर स्पष्ट करते हैं: आरोपी का रैपिडो से कोई संबंध नहीं है। वह कभी भी हमारे कैप्टन फ्लीट का हिस्सा नहीं रहा। उसका आवेदन पहले ही चरण में खारिज किया जाना ही बताता है कि उद्योग में सख्त सुरक्षा और जाँच क्यों जरूरी हैं। हम सभी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म से आग्रह करते हैं कि वे भी ऐसी ही कड़ी जाँच व्यवस्था लागू करें। रैपिडो जरूरत पड़ने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पूरा सहयोग देगा। हम एक सुरक्षित, जिम्मेदार और भरोसेमंद मोबिलिटी इकोसिस्टम बनाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं।

जमीन के विवाद में दो पक्षों में मारपीट, प्राथमिकी दर्ज

हरपुर बुदहट। थाना क्षेत्र के सोपरा गांव में जमीन और रास्ते के विवाद को लेकर ग्राम प्रधान और शिक्षक पक्ष के बीच मारपीट हो गई। लाठी-डंडे और धारदार हथियारों से हुए इस संघर्ष में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, सोपरा गांव में ग्राम प्रधान बालकेश मिश्रा और शिक्षक हरिकेश मिश्रा के बीच लंबे समय से रास्ते को लेकर विवाद चला आ रहा है। ग्राम प्रधान बालकेश मिश्रा ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि सोमवार की सुबह करीब सात बजे सार्वजनिक रास्ते पर दीवार निर्माण का विरोध करने पर शिक्षक पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें, उनके बेटे, पत्नी व बुजुर्ग मां को लाठी-डंडों से पीट दिया। इस हमले में सभी को चोटें आईं और जानमाल की धमकी भी दी गई। प्रधान की तहरीर पर पुलिस ने हरिकेश मिश्रा, गंगेश, दिनेश, कृष्णानंद, श्याम मिश्रा, इंद्रजीत, मीरा तथा गंगेश की पत्नी, सभी निवासी सोपरा, के खिलाफ बलवा, मारपीट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं, दूसरे पक्ष से शिक्षक हरिकेश मिश्रा ने पुलिस को बताया कि उनके घर के पीछे स्थित गली में उन्होंने साफ-सफाई और देखरेख के लिए खाली जमीन छोड़ रखी है। जिसे ग्राम प्रधान बालकेश मिश्रा सार्वजनिक रास्ता बताकर जबरन इंटरलॉकिंग कराने लगे। विरोध करने पर प्रधान पक्ष ने मिलकर उनके भतीजे, भाई और सहयोगी श्याम प्रसाद मिश्रा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इससे श्याम प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में पुलिस ने ग्राम प्रधान बालकेश मिश्रा, उनके बेटे सुनील मिश्रा और पत्नी गीता मिश्रा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की कोशिश की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।

ट्रैक्टर से कुचल कर बाइक सवार की मौत

कानपुर देहात (उत्तरशक्ति)। भोगनीपुर थाना के नोनापुर रोड पर मिट्टी ढुलाई के ट्रैक्टर से कुचल कर बाइक सवार की मौत हो गई। ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगा दिया। एसडीएम, सीओ, भोगनीपुर, मूसानगर थानाध्यक्ष पुलिस बल सहित पहुंचे। देवराहट थाना के सुजौर निवासी सचिन सचान (28) फतेहपुर स्थित एक प्राइवेट फैक्टरी में काम करते थे। पिता संतोष सचान का मंगलवार को निधन हो गया था। उसी में वह गांव आया था। बुधवार की शाम चार बजे वह बाइक से पुखरायां सामान लेने आ रहा था। नोनापुर रोड पर मिट्टी ढुलाई कर रहे ट्रैक्टर ने कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। हादसे व जाम लगाए जाने की जानकारी पर एसडीएम देवेंद्र सिंह, सीओ संजय वर्मा, भोगनीपुर थानाध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह, मूसानगर थानाध्यक्ष कालीचरण पुलिस बल के साथ पहुंचे। एसडीएम और सीओ मृतक के परिजनों को समझाया। सीओ संजय वर्मा ने बताया कि बाइक सवार हेलमेट लगाए थे। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

वॉट नाउ ने राज्यभर में साइबर सुरक्षा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु महाराष्ट्र साइबर के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

मुंबई। वॉट नाउ, साइबर अपराध, साइबर उत्पीड़न, सेक्सटॉर्शन तथा सभी प्रकार के ऑनलाइन दुर्व्यवहार के विरुद्ध कार्यरत एक अग्रणी एनजीओ और राष्ट्रीय जागरूकता आंदोलन, ने महाराष्ट्र राज्य में निवारक शिक्षा, डिजिटल सुरक्षा साक्षरता और जन-जागरूकता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र साइबर के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (टङ्कव) पर हस्ताक्षर किए हैं।समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में श्री यशस्वी यादव, आईपीएस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र साइबर, महाराष्ट्र सरकार की उपस्थिति रही। इस अवसर पर वॉट नाउ की संस्थापक एवं प्रसिद्ध उद्यमी सुश्री नीति गोयल; वॉट नाउ के सह-संस्थापक एवं एयू कॉरपोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज के संस्थापक अक्षत खेतान; तथा वॉट नाउ की सह-संस्थापक और पिल्लई इंस्टीट्यूट की निदेशक डॉ. निवेदिता श्रेयांस भी उपस्थित थीं। सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री अक्षत खेतान ने कहा, आज साइबर जोखिम केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और कानूनी चुनौती बन चुका है। यह साझेदारी रोकथाम, जागरूकता और नागरिकों को डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक साधनों से सशक्त बनाने पर केंद्रित है।यह सहयोग संयुक्त जागरूकता अभियानों, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और व्यापक सामुदायिक पहुंच पहलों के माध्यम से महाराष्ट्र में एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वॉट नाउ की परिकल्पना पर बोलते हुए सुश्री नीति गोयल ने कहा, वॉट नाउ की स्थापना ऑनलाइन दुर्व्यवहार के पीड़ितों की आवाज को समर्थन और मंच देने के लिए की गई थी। महाराष्ट्र साइबर के साथ यह सहयोग हमें अपनी पहुंच बढ़ाने और शिक्षा एवं जागरूकता के माध्यम से वास्तविक, जमीनी स्तर पर प्रभाव डालने में सक्षम बनाएगा। डॉ. निवेदिता श्रेयांस ने कहा, जागरूकता और शिक्षा साइबर खतरों के विरुद्ध सबसे मजबूत सुरक्षा कवच हैं। इस साझेदारी के माध्यम से हमारा उद्देश्य युवाओं और संवेदनशील समुदायों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करना है। यह सहयोग नागरिकों को सशक्त बनाने, डिजिटल विश्वास को मजबूत करने और महाराष्ट्र में एक सुरक्षित व अधिक सुदृढ़ ऑनलाइन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के साझा संकल्प को दर्शाता है।

दहिसर वार्ड-5 में सड़क पर गंदगी के खिलाफ मुहिम

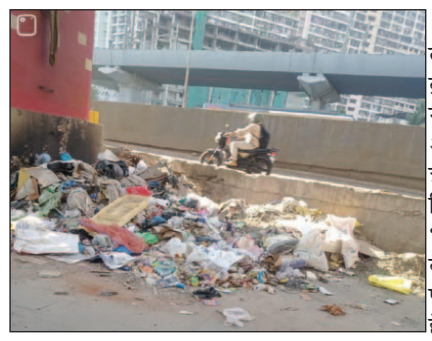

दहिसर, मुंबई। दहिसर के वार्ड क्रमांक-5 में सड़क पर गंदगी, कूड़ा-कचरा और मिट्टी से नागरिक त्रस्त रहे हैं। बार-बार शिकायत करने के बाद भी महानगरपालिका के कर्मचारी इसकी सफाई पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वहां की निवासी माया ने इसकी शिकायत उत्तर मुम्बई कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. नरेंद्र कुमार से की और उन्हें बताया कि बारिश के मौसम में उस जगह पर खुले सीवर की सफाई की गई थी और कचरा और मिट्टी निकालकर सड़कों पर डाल दी गई थी, जिसे आश्चर्यजनक रूप से

अब तक नहीं हटाया गया था। शिकायत प्राप्त होते ही डॉ. नरेंद्र कुमार ने वार्ड नंबर 5 के कार्यकताओं संग वहाँ विजिट की और स्थिति का जायजा लिया। तदुपरांत महानगरपालिका अधिकारियों से संपर्क कर उस कूड़े और मिट्टी को हटवाकर सड़क को चकाचक करवा दिया , जिससे स्थानीय नागरिकों ने राहत की सांस ली है।

डॉ. नरेंद्र कुमार ने महानगरपालिका अधिकारियों से इस वार्ड की साफ-सफाई के लिए विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया है ताकि परिसर स्वच्छ रहे और नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरित परिणाम न हो।

मोटोरोला ने लॉन्च किया अल्ट्रा-थिन फोन एज 70

पटना (उत्तरशक्ति)। मोबाइल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ग्लोबल लीडर और भारत का अग्रणी एआई स्मार्टफोन ब्रांड, मोटोरोला ने एज 70 के लॉन्च के साथ अपना सबसे पतला स्मार्टफोन पेश किया। अल्ट्रा-स्लिम इंजीनियरिंग को पुनर्परिभाषित करते हुए, डिवाइस में स्लीक 5.99 एमएम एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्युमीनियम डिजाइन है, जबकि यह एक विशाल 5000 एमएएच बैटरी देता है जो 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ देती है। इसमें फास्ट वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग, सभी लेंसों पर 4 के 60 एफपीएस रिकॉर्डिंग के साथ सेगमेंट के सबसे उन्नत ट्रिपल 50 एमपी के एआई कैमरे हैं। इस लॉन्च के मौके पर मोटोरोला इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर टी एम नरसिम्हन ने कहा कि यह स्लिम स्मार्टफोन को बिल्कुल नया रूप देता है। यह लॉन्च हमारी यात्रा का एक बड़ा कदम है। हम प्रीमियम, डिजाइन पर जोर देने वाले और एआई-संचालित अनुभव देते हैं, जो यूजर्स को ज्यादा काम करने, खुद को ज्यादा व्यक्त करने और टेक्नोलॉजी से अपनी रोज की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। मोटोरोला एज 70 सिंगल 8 जीबी रैम प्लस 256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होगा और तीन शानदार पैंटोन क्यूरेटेड रंगों - ब्रॉन्ज ग्रीन, लिली पैड, और गैजेट ग्रे में आएगा। मोटोरोला एज 70 फ्लिपकार्ट, मोटोरोला डॉट इन और प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर केवल 28,999 रुपये की प्रभावी लॉन्च कीमत पर 23 दिसंबर 2025 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

आज का महाराजगंज उपेक्षा की मार झेल रहा है, यह वही पवित्र धरती है जिसने देश के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखे थे

सिवान (उत्तरशक्ति)। महाराजगंज यही वह स्थान है जहां से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर ने जनता का विश्वास जीत कर संसद तक पहुंचने का गौरव पाया। कभी यह धरती स्वतंत्रता सेनानियों की कर्म भूमि रही। महाराजगंज की चौपालों पर बैठकर महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल, माहा माया बाबू, नारायण बाबू, चंद्रिका प्रसाद, देवशरण बाबू, किशोरी प्रसाद जी, राम लखन बाबू, बंसीलाल प्रसाद जी, और गणेश डोम जैसी महान हस्तियां देश की आजादी और भविष्य की रणनीति तय करती थीं। लेकिन विडंबना यह है कि आज वही ऐतिहासिक महाराजगंज लावारिस-सा उपेक्षित पड़ा है। न विकास की रोशनी है, न पुरानी विरासत का सम्मान। ऐसा लगता है जैसे हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस गौरवशाली इतिहास को या तो भुला दिया है या फिर जानबूझकर इसकी अनदेखी की जा रही है। आज की सबसे बड़ी जरूरत अब समय आ गया है कि महाराजगंज को जिला घोषित किया जाए, ताकि विकास की गति तेज हो सके, नई संभावनाएं खुलें, रोजगार के द्वार बनें, और यह क्षेत्र अपने खोए गौरव को फिर से पा सके। आत्मा कुमार सिंह नगर अध्यक्ष महाराजगंज जिला बनाओ संघर्ष समिति।

भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का कार्यक्रम संपन्न

वसई रोड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देशभर में हो रहे विकास कार्यों तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रगतिशील और विकासोन्मुखी विचारों पर विश्वास जताते हुए बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी के अचोले डिवीजन के पदाधिकारियों ने आज आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यह प्रवेश कार्यक्रम नालासोपारा के आमदार राजन नाईक के कार्यालय में संपन्न हुआ। इस अवसर पर भूपेंद्र आत्माराम पाटिल (पूर्व कॉर्पोरेटर), स्मिता भूपेंद्र पाटिल (सोशल वर्कर), प्रदीप गायकवाड़ (बाविया युवा अध्यक्ष), मधुकर किनी, हितेश किनी, दिनकर किनी, शिव विश्वकर्मा एवं पंकज किनी (सभी सोशल वर्कर) प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान नालासोपारा आमदार राजन नाईक के साथ वसई विधानसभा की विधायक श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित ताई, जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रज्ञा पाटिल तथा पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सभी पदाधिकारियों का पार्टी की ओर से दिल से स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक स्नेहा दुबे पंडित ताई एवं आमदार राजन नाईक ने सभी नवप्रवेशी सदस्यों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

स्नेहा दुबे पंडित की उपस्थिति में बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकताओं ने भाजपा में किया प्रवेश

वसई रोड। वसई वेस्ट स्थित वसई विधायक पब्लिक रिलेशन्स कार्यालय में बहुजन विकास अघाड़ी के कई कार्यकताओं ने भारतीय जनता पार्टी में सार्वजनिक रूप से प्रवेश किया। यह पार्टी प्रवेश कार्यक्रम स्नेहा दुबे पंडित की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर निपुण दोशी, स्वप्निल अवेरसेकर, धीरज तालेबोडी, श्रीमती निमी दोशी, राजसाहेब सिंह, रुचित कोठारी, तीर्थ दोशी, अनंत पई, सरफराज पटेल, आदर्श कनोजिया, रामकृष्ण थोरात, श्रीमती नीता जटकिया, मनोज जटकिया, देवल पांचाल, प्रज्वल सालियान, अमय पई, कौशिक पटेलिया, हित तधानी, जय सांगनी, राजेश गांधी एवं जयश गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नवनियुक्त कार्यकताओं ने भाजपा की विकासोन्मुखी नीतियों पर विश्वास व्यक्त करते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि इस प्रवेश से वसई-विरार क्षेत्र में भाजपा की ताकत और अधिक बढ़ेगी तथा आम जनता के हित में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। इस कार्यक्रम में भाजपा वसई-विरार शहर जिला महासचिव बिजेंद्र कुमार, जिला उपाध्यक्ष राजू म्हात्रे, भाजपा वर्कर्स अलायंस के जिला अध्यक्ष सिद्धेश तावड़े तथा वसई पूर्व वालिव मंडल अध्यक्ष सूर्यकांत वाघमारे भी उपस्थित रहे।

वसई-विरार में भाजपा महायुति की संयुक्त रणनीति बैठक संपन्न

नालासोपारा। नालासोपारा (पश्चिम) स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वसईझविरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के मद्देनजर महायुति की अहम संयुक्त रणनीति बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

आगामी मनपा चुनावों की पृष्ठभूमि में आयोजित इस बैठक में संगठनात्मक तैयारियों, चुनावी रणनीति, आपसी समन्वय तथा आम जनता से अधिक प्रभावी संपर्क स्थापित करने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य चुनावों में एकजुट होकर मजबूती से उतरने की रूपरेखा तय करना रहा। बैठक में वसई की विधायक स्नेहा दुबे पंडित, शिवसेना नेता व विधायक रविंद्र फाटक, नालासोपारा विधानसभा विधायक राजन नाइक, पालघर विधायक राजेंद्र गावित, बोईसर विधानसभा विधायक विलास तारे, शिवसेना जिला प्रमुख नीलेश तेंदुलकर, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रज्ञा पाटिल, शिवसेना वसई तालुका प्रमुख सुदेश चौधरी सहित महायुति के विभिन्न पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेताओं ने एक स्वर में कहा कि महायुति पूरी एकजुटता के साथ चुनाव का सामना करेगी और विकास, सुशासन तथा नागरिकों की बुनियादी समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए वसई-विरार के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।

राकपा नेता एके सिंह के निधन से फैली शोक की लहर

मुम्बई (उत्तरशक्ति)। 13 दिसम्बर को राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ए. के.सिंह के आकस्मिक निधन से उनके परिवार सहित पूरे समाज में शोक की लहर फैल गयी। मुलुंड निवासी ए. के.सिंह अपने राजनीतिक और सामाजिक सेवा कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। इस दुःखद घड़ी में उनके शोकसंतप्त परिजनों को भारी संख्या में लोगों की संवेदनायें प्राप्त हो रही है। उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील के अंतर्गत सैफाबाद पोस्ट के सुरुवार ग्राम के मूल निवासी अनिरुद्ध कुमार सिंह (ए. के. सिंह) का मुम्बई के फोर्ट क्षेत्र में ऊषा शिपिंग एजेंसी नामक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। दिवंगत ए. के.सिंह के पुत्र दीपक कुमार सिंह के अनुसार 25 दिसम्बर दिन गुरुवार को मुलुंड पश्चिम टेलीफोन एक्सचेंज के पास स्थित समृद्धि कार्सियल,मदन मोहन मालवीय रोड, एल. बी. एस. मार्ग रैली वोल्फ के पीछे समृद्धि बैंक्वेट की दूसरी मंजिल पर श्रद्धांजलि सभा एवं ब्रह्मभोज का आयोजन शाम 5 बजे से किया गया है। दीपक कुमार सिंह ने लोगों का आव्हान करते हुए कहा कि इस श्रद्धांजलि सभा एवं ब्रह्मभोज कार्यक्रम में सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। यह जानकारी वरिष्ठ पत्रकार लाल शेखर सिंह ने प्रेस विज्ञाप्ति के माध्यम से दी है।

ठंड को देखते हुए रामपुर जिले में कक्षा आठ तक के स्कूल 20 तक बंद

मुरादाबाद/रामपुर । मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड की वजह से बुधवार को स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया गया। अब कक्षा आठ तक के स्कूल सुबह दस बजे खुलेंगे। पिछले तीन दिन से पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण बच्चों को सुबह जल्दी स्कूल जाने में परेशानी हो रही थी। डीएम अनुज सिंह के अनुसार अत्याधिक शीतलहर, कोहरे के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा नर्सरी से आठ तक के सभी परिषदीय, माध्यमिक, राजकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त सभी बोर्ड के विद्यालयों का संचालन सुबह दस बजे से दोपहर तीन बजे तक किया जाएगा। सभी स्कूलों द्वारा इस आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। रामपुर जिले में दो दिन से कड़ाके की सर्दी हो रही है। मौसम विभाग ने तीन दिन तक कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर डीएम ने जिले में आठवीं तक के स्कूलों में 20 दिसंबर तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। अब स्कूल 22 दिसंबर को खुलेंगे। साथ ही आदेश नहीं मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। डीएम ने बताया कि यह अवकाश सरकारी, अर्द्धसरकारी और निजी स्कूलों के लिए है।

हाईकोर्ट में PIL की खबर से अटाला मस्जिद की दुकानदरों में मचा हड़कंप

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जनपद की ऐतिहासिक अटाला जामा मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में है। मस्जिद परिसर में बनी दुकानों को ध्वस्त किए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रयागराज में जनहित याचिका दायर होने की खबर मिलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया है।

जौनपुर का अटाला मस्जिद बीते कई वर्षों से सुर्खियों में है, स्वराज वाहिनी संस्था के संतोष मिश्रा नामक व्यक्ति ने अटाला जामा मस्जिद परिसर में बनी करीब 50 दुकानों के ध्वस्तीकरण की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को जनहित याचिका (PIL) के रूप में सुनवाई योग्य मानते हुए कहा है कि मामला जनहित से जुड़ा है, इसलिए इसकी सुनवाई PIL के तौर पर की जाएगी। जनहित याचिका दायर होने के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। दुकानदार शमीम अहमद का दावा है कि वे 50 वर्षों से भी अधिक समय से यहां दुकानें खोलकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। अचानक ध्वस्तीकरण की मांग ने उनकी रोजी-रोटी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय नागरिक कमाल आजमी का आरोप है कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देकर हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि असल सवाल आजीविका और विरासत से जुड़ा है।

उद्यान विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत दो दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिला उद्यान अधिकारी ने अवगत कराया है कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना वर्ष 2025-26 अन्तर्गत 17 व 18 दिसम्बर, 2025 को दो-दिवसीय जनपद स्तरीय कृषक गोष्ठी/सेमिनार/किसान मेला/भ्रमण का आयोजन कृषि विज्ञान केन्द्र बक्शा पर आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य उ0प्र0 स्थानीय निकाय जौनपुर बृजेश सिंह (प्रिन्सू) द्वारा दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। जिला उद्यान अधिकारी डा० सीमा सिंह, राणा द्वारा उद्यान विभाग द्वारा जनपद में संचालित योजनाये यथा- एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत फल, शाकभाजी, मशाला, पुष्प की खेती, मशरूम उत्पादन इकाई, पालीहाउस शेडनेट हाउस लगवाकर किसान अपनी को दोगुना कर सकते है। पर ड्राप मोर क्राप माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत ड्रिप इरीगेशन, मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम लगाकर कृषक समय, श्रम

और पानी की बचत करते हुए उत्पादन को बढा सकते है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत खाद्य प्रंसस्करण उद्योग लगाने पर 35 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है।

कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र अमहित के वैज्ञानिक डा0 आर0 के0 सिंह ने औद्यानिक खेती की नवीन तकनीको आलू व आम में इस वक्त किसान क्या करें के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक डा0 सुरेश कन्नौजिया ने कृषको को पराम्परगत खेती से हटकर तकनीकी खेती के साथ जैविक खेती को अपनाने का कृषको से आवाहन किया। मुख्य अतिथि जी ने कृषको को विभाग से जुडकर संचालित योजनाओ से लाभ लेने हेतु प्रेरित कर नयी-नयी तकनीको का प्रयोग कर अपनी आय को तिगुना करने की अपील की। मुख्य अतिथि महोदय को प्रगतिशील कृषको द्वारा उपहार स्वरूप उत्पाद दिये गये साथ ही साथ जनपद के प्रगतिशील कृषको को उनके उत्कृष्ट उत्पादन के लिए सम्मानित किया गया जिसमें विकासखंड रामपुर संजय मिश्रा, विकासखंड जलालपुर लाल बहादुर मौर्या, विकासखंड बदलापुर विजय प्रताप, विकासखंड महाराजगंज धनन्जय गुप्ता, विकासखंड खुटहन विजय बहादुर सिह को शाल व शील्ड देंकर सम्मानित किया गया। पी0एम0एफ0एम0ई0 योजनान्तर्गत उद्यामियों को मशाला व डेरी उद्योग के लिए डमी चेक का वितरण किया गया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के कर कमलो द्वारा जनपद के प्रगतिशील कृषकों को निःशुल्क सब्जी बीज वितरण (कैरला, टमाटर, ,खीरा, लौकी) का वितरण कराया गया। कार्यक्रम का संचालन परियोजना निदेशक आत्मा डॉ0 रमेश चंद्र यादव द्वारा किया गया। विभागीय कर्मचारी कार्यक्रम मे उपस्थित रहें।

सामाजिक उत्थान एवं एकता महासम्मेलन संपन्न

मुंबई। सामाजिक संगठन नई उम्मीद फाउंडेशन ट्रस्ट (मुंबई महाराष्ट्र), नंदवंशी सेल्फ केयर ट्रस्ट एवं सर्व सहयोग सेवा ट्रस्ट के संयुक्त संयोजन में 13 दिसंबर 2025 को संतसेना महाराज सभागृह दादर मुंबई में सामाजिक उत्थान एकता महासम्मेलन तथा समाज रत्न गौरव सम्मान समारोह संपन्न हुआ जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष महापद्मनंद वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय प्रचारक ठरऊळ तथा राष्ट्रीय सेवा रत्न अवार्ड से सम्मानित वरिष्ठ समाजसेवी घनश्याम शर्मा अमेठी उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथियों में दिनेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष भारतीय नई कल्याण विकास सेवा समिति, उदय राज शर्मा सचिव MWO को उत्तर प्रदेश, शिवदयाल शर्मा महासचिव MWO, मुन्ना लाल शर्मा ब्लाक अध्यक्ष एवं संगठन मंत्री MWO, शैलेंद्र शर्मा प्रदेश संरक्षक नई उम्मीद फाउंडेशन एवं NSCT संयोजक वाराणसी, नामदेव विट्ठल झिंगाड़े अध्यक्ष प्रेरणा चैरिटेबल ट्रस्ट, कल्याण चंदू मुजूमुले लाइफ कोच एवं पूर्व रएड महाराष्ट्र,उदय टक्के सर हेयर आर्टिस्ट, प्रसाद चौहान महाराष्ट्र अध्यक्ष SBPA,रमेश चौहान अध्यक्ष SBPA ठाणे जिला,पवन कोतवाल (स्वतंत्रता सेनानी हुतात्मा वीर भाई कोतवाल नातू), कवि,गीतकार एवं पत्रकार विनय शर्मा दीप,ओमप्रकाश सविता,कलेक्टर शर्मा, अशोक शर्मा, नीलम शर्मा भाजपा सायन कोलीवाड़ा महिला मोर्चा अध्यक्ष एवं राधा संतोष शर्मा भाजपा ठाणे महिला मोर्चा उपाध्यक्ष मुख्य रूप से उपस्थित थे। उक्त समारोह में मुंबई एवं उप नगरों से जियालाल शर्मा, संतोष निरंकार शर्मा, हरिकेश नंदवंशी, प्रदीप नंदवंशी, अधिवक्ता अनिल शर्मा,राम मिलन शर्मा,संतोष कुमार शर्मा, अशोक शर्मा कलवा,मनोज शर्मा, अमरनाथ शर्मा सहित सैकड़ों समाजसेवी उपस्थित थे। समारोह का शुभारंभ संत सैनजी महराज की प्रतिमा पर अतिथियों द्वारा पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्ज्वलित करके किया गया तत्पश्चात कवि विनय शर्मा दीप ने स्वागत गीत से सभी का सम्मान किया। मंच का संचालन शिक्षाविद रविन्द्र शर्मा ने किया तथा सभी का सम्मान खूबसूरत शब्दों, मोमेंटो, अंगवस्त्र तथा पुष्पगुच्छ देकर किया गया।उक्त समारोह के संयोजक घनश्याम शर्मा, चंद्रभूषण शर्मा,अनिल कुमार मुन्ना लाल शर्मा, सत्य कुमार शर्मा, श्यामजी शर्मा, रोशन शर्मा, अनिल कुमार शर्मा एवं आशीष मुन्ना लाल शर्मा सहित सहयोगी अवधेश शर्मा, प्रेम कुमार शर्मा, रामजनम शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा, राजेश शर्मा एवं दुर्गेश शर्मा उपस्थित थे। अंत में घनश्याम शर्मा ने उपस्थित सभी समाजसेवी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

उत्कृष्ट साहित्य जीवन के स्वर्णिम द्वार खोलने में सहायक : डॉ .अंशुल

वरिष्ठ साहित्यकार जटाशंकर प्रियदर्शी को साहित्यकार सत्कार: आपके द्वार योजना में मिला साहित्य रत्न सम्मान

प्रयागराज (उत्तरशक्ति)। उत्कृष्ट साहित्य सर्जक की लेखनी से निसृत विचार शब्दों के रूप में जीवन के स्वर्णिम द्वार खोलने में सहायक होता है जो मनुष्य को उजार्वान बनाए रखता है । उपरोक्त उद्गार सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ शंभूनाथ त्रिपाठी अंशुल ने उस समय व्यक्त किए जब वह साहित्यांजलि प्रकाशन द्वारा साहित्यकार सत्कार आपके द्वार योजना में रसूलाबाद संजय चौराहे के पास मशहूर कवि साहित्यकार जटाशंकर प्रियदर्शी के आवास पर अध्यक्षीय उद्बोधन कर रहे थे तथा कहा कि प्रियदर्शी को साहित्य रत्न सम्मान मिलना साहित्य जगत में गौरव की बात है। अपने स्वागत भाषण में डॉ राम लखन चौरसिया वागीश ने कहा कि प्रियदर्शी को सम्मानित कर संस्था खुद गौरवान्वित है शब्द और सृजनकार सदैव अमर रहते हैं वे कभी नहीं मरते इसीलिए केवल रचनाकार और ब्रह्म को सृजनकर्ता की संज्ञा दी गई है। साहित्यांजलि प्रकाशन प्रयागराज के व्यवस्थापक डॉ० भगवान प्रसाद उपाध्याय के संचालन में सम्पन्न इस आयोजन में पं.राकेश मालवीय मुस्कान ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया और विख्यात कवि- कलाकार रवीन्द्र कुशवाहा ने योजना पर विस्तार से जानकारी दी। कुशवाहा ने साहित्यिक सर्जना की मासिक पत्रिका साहित्यांजलि प्रभा को संरक्षित संवर्धित करने की अपील की। इस अवसर पर जटाशंकर प्रियदर्शी ने अपनी कविताओं का सस्वर पाठ किया और सम्मान योजना के दीघार्यु होने की कामना करते हुए कहा कि यह पूरे देश में अपनी तरह की अनूठी पहल है। उपस्थित सभी सम्मानित कवियों ने अपनी कविताओं से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में आभार डॉ भगवान प्रसाद उपाध्याय ने व्यक्त किया।

प्रो.विजय बहादुर सिंह शिक्षकों और छात्र-छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत: हृदय प्रसाद सिंह

सुइथाकला, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। क्षेत्र के गांधी स्मारक विद्यालय संकुल प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष, गांधी स्मारक पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य, भूगोल विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. विजय बहादुर सिंह का बुधवार की सुबह लखनऊ मेदांता में इलाज के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया। एक सप्ताह से उनका इलाज चल रहा था। संकुल की सभी शाखाओं में शोक सभा आयोजित करके भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। प्रो. सिंह 90 वर्ष के थे। श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से उन्होंने अध्यापन कार्य की शुरूआत की। इसके पश्चात भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष रहे और प्राचार्य के पद पर भी कार्यरत रहे। श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक सतीश सिंह सरकारी स्कूल में शिक्षक व संतोष सिंह अमेरिका के कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में एप्पल कंपनी के निदेशक हैं और पत्नी रीता देवी पूर्व प्रधान रह चुकी हैं। उनके निधन पर प्रबंधक हृदय प्रसाद सिंह रानू ने गहरा दुख जताया है। प्रबंधक ने कहा कि विजय बहादुर सिंह का निधन विद्यालय परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वह विद्यालय प्रबंध समिति के लिए एक मजबूत स्तंभ ही नहीं बल्कि नींव थे। प्रबंधक ने उन्हें एक योग्य एवं आदर्श शिक्षक बताया।

CLAT-2026 में समीक्षा सिंह की शानदार सफलता, ऑल इंडिया 45वीं रैंक से बढ़ाया जौनपुर का मान

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिले की होनहार बेटी समीक्षा सिंह ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT)-2026 में संपूर्ण भारत में 45 वां स्थान प्राप्त कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जौनपुर जनपद का नाम रोशन किया है। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि से जिले में खुशी और गर्व का माहौल है। समीक्षा सिंह मूल रूप से ग्राम फत्तूपुर, पोस्ट बदलापुर, जनपद जौनपुर की निवासी हैं। वह बदलापुर के प्रतिष्ठित शिक्षाविद् स्वर्गीय शेर बहादुर सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य सल्तनत बहादुर इंटर कॉलेज की सुपौत्री हैं। इसके साथ ही वह पूर्व ब्लॉक प्रमुख बदलापुर ओमप्रकाश सिंह एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती माधुरी सिंह की नातिन हैं। समीक्षा के पिता नीलेश सिंह एवं माता श्रीमती रजनी सिंह ने बेटी की इस सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि उसकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने बताया कि समीक्षा शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं और कानून के क्षेत्र में आगे बढ़कर देश की सेवा करने का सपना संजोए हुए हैं। समीक्षा सिंह की सफलता की खबर मिलते ही परिवार, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों द्वारा बधाइयों का तांता लग गया। क्षेत्र के गणमान्य लोगों और शिक्षाविदों ने भी उनकी इस उपलब्धि को जौनपुर जिले के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए उनके उज्वल भविष्य की कामना की है।

जफराबाद में दिल दहला देने वाला डबल मर्डर

बेटे ने ही माता-पिता की हत्या कर शवों के टुकड़े कर गोमती में फेंके, आरोपी गिरफ्तार

जफराबाद, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। थाना जफराबाद क्षेत्र के अहमदपुर गांव में सामने आया दोहरा हत्याकांड पूरे जिले को झकझोर देने वाला है। श्यामबहादुर और उनकी पत्नी बबिता देवी की निर्मम हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उनके ही 36 वर्षीय पुत्र अम्बेश कुमार उर्फ रिंकू ने की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त औजारों और कार को बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार यह घटना 8 दिसम्बर 2025 की शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच हुई। पैसे और पारिवारिक विवाद को लेकर अम्बेश का अपनी मां से झगड़ा हुआ। मां द्वारा घर छोड़ने को कहने पर गुस्से में आकर उसने लोहे के खल-बट्टे की रॉड से मां के सिर पर हमला कर दिया। इसी दौरान पिता श्यामबहादुर पुलिस को फोन करने लगे, तो आरोपी ने उन पर भी उसी रॉड से वार किया और बाद में रस्सी से गला कसकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के इरादे से दोनों शवों को लोहे की आरी से तीन-तीन टुकड़ों में काटा। शवों के टुकड़ों को छह प्लास्टिक बोरियों में भरकर, खून व अन्य अवशेष अलग बोरी में रखकर अपनी स्विफ्ट डिजायर कार (UP62 BV 6304) से भोर में बेलाव पुल से गोमती नदी में फेंक दिया। घर और गाड़ी को सर्फ से धोकर साफ किया गया। बाद में घर में छूटे मां के कटे पैर को आरोपी ने जलालपुर ले जाकर सई नदी में फेंक दिया। घटना के बाद आरोपी ने बहनों को गुमराह करते हुए बताया कि माता-पिता कहीं चले गए हैं। बहनों के दबाव और डर के चलते उसने मोबाइल बंद कर जौनपुर स्टेशन और वाराणसी के गंगा घाटों पर कई दिन बिताए। 15 दिसम्बर को घर लौटने पर बहनों से पूछताछ में उसने पूरी वारदात स्वीकार कर ली। इसके बाद दूसरी बहन अर्चना की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया।

सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री गोल्डी गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना जफराबाद पुलिस ने 16 दिसम्बर 2025 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त खल-बट्टे की रॉड, रक्तरंजित आरी, लोढ़ा, कपड़े, मोबाइल फोन, कार से जुड़े साक्ष्य सहित बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद की गई। यह सनसनीखेज हत्याकांड न केवल क्षेत्र में दहशत का कारण बना है, बल्कि पारिवारिक रिश्तों को भी शर्मसार करने वाला साबित हुआ है।

रोहनिया विधायक की पहल पर गांधी स्मारक के पुन: निर्माण हेतु समस्या का समाधान

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। रोहनिया चौराहा पर जीटी रोड चौड़ीकरण के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा गांधी स्मारक चबूतरा को तोड़कर हटा दिया गया था जिसको लेकर पीडब्लूडी विभाग द्वारा बाजार वासियों को आश्वासन दिया गया था कि जिस तरह हम इसे यहां से हटा रहे है सड़क चौड़ीकरण निर्माण के बाद पुनः उसी स्थान पर पहले जैसा गांधी स्मारक बनाकर बाजार वासियों को सौंप देंगे लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ जिसको लेकर व्यापारियों में काफी नाराजगी रही। व्यापार मंडल अध्यक्ष दशमी यादव ने कहा कि मेरे द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग के संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जिसे अधिकारियों द्वारा सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिया गया लेकिन अभी तक निर्माण नहीं किया गया। जिससे नाराज व्यापारियों ने रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल को इस समस्या से अवगत कराया उक्त समस्या की समाधान के लिए रोहनिया व्यापार मंडल अध्यक्ष दसमी यादव के नेतृत्व में उपस्थित व्यापारियों के बीच रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल ने पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ अभिनेश गंगवार को मौके पर बुलाकर उनसे वार्ता कर समस्या का हल निकाला।रोहनिया बाजार में निरीक्षण के दौरान व्यापारियों द्वारा किए गए चिन्हित स्थान पर गांधी स्मारक चबूतरा बनाने हेतु एवं रोहनिया चौराहे पर एक्सीडेंट से राहत पाने हेतु मोहनसराय से कैंट जाने वाली जीटी रोड पर ब्रेकर लगाने हेतु निर्देशित किया। इस दौरान प्रमुख रूप से रोहनिया थाना प्रभारी राजू सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष दसमी यादव, राष्ट्रीय सचिव अपना दल एस अजीत पटेल, मानस सिंह,प्रमोद सिंह ,ओम प्रकाश जायसवाल, कृष्णकांत मिश्रा, अजय शर्मा, घनश्याम वर्मा पूर्व प्रधान, महेंद्र यादव, सदानंद पटेल, विजय पटेल, बाबा सिंह, शिव लखन पटेल, सुक्खु पटेल, सुरेश मोदनवाल ,अनिल मिश्रा, विजय मोदनवाल, अंकित वर्मा, रोशन सिंह, तेजू गुप्ता इत्यादि व्यापारीगण उपस्थित रहे।

राजेश मिश्रा को मिली भाजपा जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी

भायंदर। भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप जैन द्वारा राजेश मिश्रा को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें यह नियुक्ति पत्र विधायक नरेंद्र मेहता व जिला अध्यक्ष दिलीप जैन के हाथों प्राप्त हुआ। राजेश मिश्रा भाजपा के एक कर्मठ और ऊजार्वान कार्यकर्ता होने के साथ-साथ वरिष्ठ समाजसेवी भी रहे हैं। समय समय पर धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करते रहे हैं। श्री मिश्र इसके पहले जिला सचिव पद संभाल चुके हैं। राजेश मिश्रा ने कहा कि वे दी गई जिम्मेदारियां का निर्वहन पूरे मनोयोग के साथ करेंगे । राजेश मिश्रा को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने से भाजपा कार्यकताओं एवं उत्तर भारतीय समाज में खुशी की लहर फैल गई। बधाइयों का ताता लगा हुआ है। भाजपा उपाध्यक्ष सुरेश सिंह, वरिष्ठ समाजसेवक रत्नाकर मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता एड डीके पांडेय, भाजपा नेता रमेश मिश्रा, धर्मेंद्र चतुवेर्दी, पूर्व नगरसेवक मनोज रामनारायण दुबे, विजय राय, स्नेहा पांडे, प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडेय , महिला जिला अध्यक्ष वैशाली भोईर, रेनू मल्लाह काजल सक्सेना, अनीता राय, पूजा विश्वकर्मा, महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रावती त्रिपाठी, उत्तर भारतीय मोर्चा महामंत्री कमलेश दुबे, महेंद्र पांडेय, सुरेन्द्र तिवारी, एड पी आर शुक्ला, एड मनीष तिवारी सहित अनेक गणमान्य लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी है।

मीरा भायंदर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष बनाए गए सुरेश सिंह

भायंदर। भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप जैन ने उत्तर भारतीय मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष तथा लोकप्रिय उत्तर भारतीय नेता सुरेश सिंह को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। विधायक नरेंद्र मेहता व जिला अध्यक्ष दिलीप जैन के हाथों उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी रत्नाकर मिश्रा, रमेश चंद्र मिश्रा, पूर्व नगरसेवक मनोज रामनारायण दुबे, उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष संतोष दिक्षित, भाजपा नेता राजेश मिश्रा, मोर्चा के महामंत्री कमलेश दुबे, प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे, ओम प्रकाश सिंह समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। सुरेश सिंह भाजपा के कर्मठ, ऊजार्वान,सर्वप्रिय तथा विनम्र चेहरा के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर भारतीय संघ, मीरारोड शाखा के अध्यक्ष रहे सुरेश सिंह को 2016 में तत्कालीन विधायक नरेंद्र मेहता ने भाजपा की सदस्यता दिलाई थी। तभी से वे पार्टी के लिए लगातार सक्रियता से काम कर रहे हैं। सुरेश सिंह इस शहर के नामचीन भवन निमार्ता के साथ साथ लोकप्रिय समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। कोविड संकट काल के समय उनके द्वारा की गई मानवीय सहायता को लोग आज भी याद करते हैं। पार्टी द्वारा 2022 में सुरेश सिंह को उत्तर भारतीय मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में शहर के अनेक उत्तर भारतीय भाजपा से जुड़े।उन्हें दूसरा कार्यकाल भी मिला । 2024 विधानसभा चुनाव में पार्टी के निर्णायक विजय को सुनिश्चित करने में वे सबसे आगे रहे। महानगरपालिका चुनाव को देखते हुए अब सुरेश सिंह को जिला उपाध्यक्ष नियुक्ति के साथ साथ प्रभाग 18 का प्रभारी बनाकर पार्टी के सभी उम्मीदवारों जिताने की विशेष जवाबदारी दी गई है। सुरेश सिंह को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने से भाजपा कार्यकताओं एवं उत्तर भारतीय समाज में खुशी की लहर फैल गई। बधाइयों का ताता लगा हुआ है। वरिष्ठ अधिवक्ता एड डी के पांडेय, धर्मेंद्र चतुवेर्दी, विजय राय, पूर्व नगरसेविका स्नेहा पांडे, महिला जिला अध्यक्ष वैशाली भोईर, रेनू मल्लाह, काजल सक्सेना ,अनीता राय, पूजा विश्वकर्मा, पूर्व जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष चंद्रावती त्रिपाठी, महेंद्र पांडेय, युवा मोर्चा महामंत्री विवेक उपाध्याय, अजीत उपाध्याय, सुरेन्द्र तिवारी, एड पीआर शुक्ला, एड मनीष तिवारी समेत अनेक लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी है।

ठंड से राहत के लिए जौनपुर में रैन बसेरे व अलाव की व्यवस्था, एडीएम ने किया औचक निरीक्षण

जौनपुर (उत्तरशक्ति) । प्रदेश सरकार के निर्देश पर जनपद में शीतलहर व गलन से लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर रैन बसेरे एवं अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी गई है, ताकि जरूरतमंदों, यात्रियों एवं असहाय लोगों को ठंड से राहत मिल सके। नगर पालिका परिषद जौनपुर द्वारा रोडवेज बस स्टैंड परिसर में रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। यहां कुल 16 चारपाइयां लगाई गई हैं, जिन पर अच्छी गुणवत्ता की रजाइयां एवं गद्दे उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए अलाव की भी व्यवस्था की गई है। रैन बसेरे की साफ-सफाई एवं रखरखाव के लिए रोडवेज परिसर के कर्मचारियों की तैनाती की गई है। रैन बसेरे की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अपर जिलाधिकारी (वित्त/ राजस्व) अजय अंबष्ट ने रोडवेज परिसर स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से पूछताछ की तथा आगंतुकों के रजिस्टर की भी जांच की। उन्होंने व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीएम अजय अंबष्ट ने बताया कि शासन से स्पष्ट निर्देश प्राप्त हैं कि ठंड के कारण किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इसी के तहत जनपद के सभी 12 नगर निकायों में रैन बसेरे एवं अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जौनपुर नगर में बस स्टैंड पर नगर पालिका परिषद द्वारा रैन बसेरा संचालित किया जा रहा है, जहां पर्याप्त संख्या में बिस्तर, चादर, बेड, पीने के पानी तथा शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध है। यदि कोई यात्री रात में घर नहीं जा पाता है तो वह यहां सुरक्षित एवं आरामदायक ढंग से विश्राम कर सकता है। उन्होंने बताया कि नगर के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि अलाव को लेकर कुछ स्थानों पर प्रारंभिक दिक्कतें हैं, लेकिन जहां अत्यधिक आवश्यकता है, वहां अलाव जलाए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरे की व्यवस्था के संबंध में एडीएम ने बताया कि गत वर्ष रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरा लगाया गया था, लेकिन इस वर्ष रेलवे अधीक्षक द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई है। इसके लिए रेलवे प्रशासन को अपने उच्च अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। इस विषय पर रेलवे अधिकारियों से लगातार वार्ता की जा रही है और शीघ्र ही अनुमति मिलने पर रेलवे स्टेशन परिसर में भी रैन बसेरे की व्यवस्था कर दी जाएगी।

प्रयागराज से पधारे प्रसिद्ध भागवताचार्य संत श्री सर्वेश जी प्रपन्नाचार्य जी महाराज का बदलापुर आगमन पर श्रद्धालुओं द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर शिक्षाविद् बालगोविंद तिवारी ने संत श्री के दर्शन किए तथा उनके साथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर गहन चर्चा की। छाया: उत्तरशक्ति

कंबल मिलते ही लाभार्थियों के चेहरे पर आई मुस्कान

-आदेश मिश्र

सुल्तानपुर। गरीबों के मसीहा रहे स्वर्गीय चंद्रशेखर शुक्ल बेबी भइया द्वारा आरंभ की गई सेवा परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोकाधिकार सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल रिंकू भइया के मार्गदर्शन में समिति के राष्ट्रीय महासचिव एवं जयसिंहपुर ब्लॉक प्रमुख राहुल चंद्रशेखर शुक्ल ने बुधवार को सुलतानपुर के जयसिंहपुर तहसील स्थित कोल्हुआमऊ, अर्जुनपुर, ककरवारपुर एवं चौधरी का पुरवा (निषाद बस्ती) में असहाय, विधवा, वृद्ध एवं दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क कंबल वितरण शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ समिति के संस्थापक एवं समाज के पुरोधा, समाज रत्न एवं महाराष्ट्र गौरव से सम्मानित स्वर्गीय चंद्रशेखर शुक्ल बेबी भइया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके उपरांत ब्लॉक प्रमुख राहुल चंद्रशेखर शुक्ल द्वारा हजारों की संख्या में जरूरतमंद लाभार्थियों को निःशुल्क कंबल वितरित किए गए। कंबल प्राप्त करते ही लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी और संतोष की झलक साफ दिखाई दी। गौरतलब है कि लोकाधिकार सेवा समिति विगत 21 वर्षों से शीत ऋतु में जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित करती आ रही है। हाल ही में समिति द्वारा बरौसा चौराहे पर विगत वर्ष की भांति इस 21वें वर्ष भी शिविर लगाकर निःशुल्क नेत्र परीक्षण, चश्मा वितरण एवं निःशुल्क कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर ग्राम प्रधान शैलेन्द्र यादव, प्रधान कर्मवीर निषाद, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रवि शेखर, रवि तिवारी, सुजीत तिवारी, अंजनी यादव, महेश यादव, रंजीत निषाद, प्रमोद प्रजापति, जगराम निषाद, समर अकेला, दिलीप पाल, शिवप्रसाद पाल, सुनील निषाद, नन्हकऊ निषाद, विपिन सिंह, परमानंद पाल, सोनू, अमन एवं रामदौर निषाद सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी एवं ग्रामवासी मौजूद रहे।

दैनिक उत्तर शक्ति समाचार पत्र के उपसंपादक प्रेम चंद मिश्रा ने इंदौर के दशहरा मैदान के सामने सम्माननीय समाजसेवी प्रणीत तिवारी से मुलाकात कर दैनिक उत्तर शक्ति समाचार पत्र को इंदौर में विस्तार के लिए चर्चा किया , साथ में दाएं से राधेश्याम शर्मा, दैनिक उत्तर शक्ति समाचार पत्र के उपसंपादक प्रेम चंद मिश्रा , समाजसेवी प्रणीत तिवारी, दिपेश पाण्डेय, व्यवसायी राजा अरोड़ा के साथ औपचारिक मुलाकात की । जिसमें समाचारपत्र के विस्तार और विकास के लिए चर्चा हुई और लोगों ने विश्वास दिलाया कि हम सब मिलकर अखबार को आगे बढ़ाएंगे।